साप्ताहिक
शांति मिशन
नई दिल्ली
वर्ष-29 अंक- 16 17 - 23 अप्रैल 2022 पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए
जातिविहीन भारत की कल्पना पृष्ठ - 6
यौन अपराध संकट में पड़ते बच्चे पृष्ठ - 7

कश्मीरी पंडितों की हत्या पर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म

द कश्मीर फाइल्स

ऐतिहासिक तथ्यों को छिपाने का असफल प्रयास

इस फिल्म में आतंकवाद के शिकार अन्य धर्मों के लोगों को जिस तरह नज़र अंदाज़ किया गया उसने खुद कश्मीरी पंडितों की हत्या पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।

हाल में सम्पन्न यू.पी. उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के विधान सभा चुनाव के परिणाम और उनमें पंजाब के अलावा बाकी चारों राज्यों में भाजपा की खुशी का गुलाल अभी गिला भी नहीं हुआ था कि भाजपा और उसके पालतू कुछ लोग 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गए है। इस तैयारी की शुरूआत एक बार फिर उन्होंने हिन्दू और मुसलमानों के नाम पर ही की है। अभी हाल में एक फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' के नाम आई हो तकरीबन पूरे देश में प्रदर्शित हो रही है जिसमें फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने 1989 में कश्मीरी पंडितों पर आतंकवादी हमलों की वजह से लाखों कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ने पर मजबूर कर दिए गए थे, जो आज भी घाटी से बाहर ही पड़े हुए हैं और बेकसी की ज़िन्दगी बिता रहे हैं।

इस फिल्म की कहानी एक नौजवान कश्मीरी पंडित कृष्ण के आसपास घूमती है जो अपने दादा की आख़िरी इच्छा पूरी करने के लिए कश्मीर जाता है। उसके दादा की आख़िरी इच्छा यह थी कि उसकी राख उसके बुजुर्गों के उस घर पर बिखेरी जाए जिसे जनवरी 1990 में उन्होंने छोड़ देने के लिए मजबूर कर दिया गया था। उस नौजवान कृष्णा को कश्मीर में दो दिन के आवास के दौरान कश्मीरी पंडित पर होने वाले अत्याचारों के बारे में पता चलता है जिनसे उनके परिवार के लोग मारे गए थे। विवेक अग्निहोत्री की यह फिल्म केवल उसके लिए नहीं बनाई गयी कि कश्मीरी पंडितों की हालत लोगों के सामने आए बल्कि आज तीस वर्ष बाद फिल्म को बनाना उनके सांप्रदायिक एजेंडे को पेश करने की अलामत भी साफ दिख रही है। वह स्वयं भी इस घटना का प्रयोग फिल्म को धर्मनिरपेक्ष राजनैतिक नेताओं को इस बात पर निन्दा और रूसवा करते नज़र आते हैं जो मुसलमानों पर अत्याचार के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। अग्निहोत्री ने कम्युनिस्टों की भी ऐसी सूरत पेश की है जो या कश्मीरी पंडित पर होने वाले अत्याचारों से अनजान हैं और या फिर वह नाउम्मीदी का शिकार हैं।

यह किस क़दर हैरत की बात है कि फिल्म देखने वालों ने अग्निहोत्री के इस ख़ालिस, खालिस राजनैतिक एजेंडों को जो केवल साम्प्रदायिक ताक़तों में जोर पैदा करने वाला है हाथो हाथ लिया है और उस पर अपनी पसंद के इज़हार के साथ साथ सिनेमाघरों में काफी उग्र नारों के साथ मुसलमानों को गालियों से नवाज़ा गया है लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अग्निहोत्री के राजनैतिक एजेंडे के विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं और अग्निहोत्री पर इतिहास के पन्नों के साथ ग़लत छेड़छाड़ करने का आरोप लगा रहे हैं। कुछ लोग खुद फिल्म के कैरेक्टर अनुपम खेर का 2013 का एक क्लिप्स भी शेयर कर रहे हैं जिसमें उन्होंने इस मुद्दे पर कहा था कि "मैं कुछ लोगों को कश्मीरी पंडितों की नक़ल करने पर शोर हंगामें को धार्मिक हिंसा में बदलते देख रहा हूं जबकि ऐसा नहीं है यह केवल एक इंसानी तकलीफ का मामला है, चाहे तकलीफ हिन्दू को हो या मुसलमान को' अनुपम खेर ने जिस साम्प्रदायिक विभाजन पर अपनी चिंता जताई थी आज खुद उनकी निगरानी में बनने वाली फिल्म के माध्यम से वह सामने आ रही है। वायरल होने वाले क्लिप्स में फिल्म को देखने वाले इस फिल्म से प्रभावित होकर मुसलमानों को गालियां भी दे रहे हैं, और उन्हें क़त्ल की धमकियां भी दे रहे हैं। साथ ही मुस्लिम फिल्मसाजों और रोल वाली फिल्मों के बायकॉट की अपीलें भी की जा रही हैं। राजधानी दिल्ली के एक सिनेमाघर में एक व्यक्ति कह रहा है कि जब तक धर्मनिरपेक्ष भारत है तब तक हिन्दू मारे जाते रहेंगे वह उन राज्यों में हिन्दुओं का भविष्य अंधकारमय बता रहा है जहां भाजपा को वोट नहीं मिलते।

भाजपा इस फिल्म को हिन्दू मुस्लिम में घृणा फैलाने के लिए इस्तेमाल करने सफल रही है। भाजपा सत्ता वाले राज्यों में फिल्म देखने वाले पुलिसवालों को छुट्टी भी दे रही है फिल्म रिलीज होने के एक दिन बाद 12 मार्च को अग्निहोत्री और उनकी बीवी ने खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी से मुलाकात कि और केवल पहले के दो दिन की कमाई को 15 करोड़ तक पहुंचा दिया, इस मूवी को मोदी का भी आर्शीवाद प्राप्त हुआ उन्होंने 15 मार्च को भाजपा संसदीय बोर्ड की मीटिंग को संबोधित करते हुए बड़े अहंकार से कहा कि "ऐसी और भी फिल्में बननी चाहिए, जो लोग व्यक्तिगत आज़ादी का झंडा उठाए घूम रहे थे पिछले कुछ दिनों से वह बौखलाए हुए हैं, हकाएक और कलाकारी के आधार पर फिल्म का विश्लेषण करने के बजाए वह फिल्म को बदनाम करने का अभियान छेड़े हुए हैं, मेरा मुद्दा फिल्म नहीं है मेरी सोच यह है कि सच जो भी हो उसे देश की भलाई के लिए सही तौर पर पेश करने की आवश्यकता है और अगर कोई चाहे तो उसी मुद्दे पर अपने दृष्टिकोण से एक और फिल्म ला सकता है।"

हमारे प्रधानमंत्री ने जो भी कहा वह ठीक ही कहा इसलिए कि वह प्रधानमंत्री हैं और वह जिस नज़रिए की अगुआई करते हैं उसमें उनकी बात से इंकार जुर्म समझा जाता है। मगर बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वह अपनी पर क़ायम रहते हुए क्या गुजरात दंगों 2002 पर राहुल ढोलकिया की फिल्म "परजानिया" को गुजरात में दिखाने की अनुमति देंगे जिसे वहां सिनेमाघरों में मालिकों ने दिखाने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया था कि गुजरात के कट्टरपंथी हिन्दू उनके विरोधी हो जाएंगे इसलिए कि इस फिल्म में गुजरात नरसंहार की एक हल्की सी तस्वीर पेश की गयी थी।

> **इस सत्यता से इंकार नहीं किया जा सकता कि पिछले आठ दस सालों में फिल्में भी राजनीति से प्रेरित होती जा रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य में 'पदमावती' फिल्म के दिखाए जाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने "केदारनाथ" को नहीं दिखाने दिया कि एक हिन्दू लड़की और एक मुस्लिम लड़के बीच प्यार की कहानी पर था। हिन्दू नफ़रत पसंदों की सरकार में तकलीफ से परेशान काल्पनिक भारत पर बनाई गई 'नेटफिलिक्स' की वेब सीरीज लिल्ली का सीजन-2 तो हिन्दू कट्टरवादियों के डर से प्रदर्शित ही नहीं किया जा सका था। कश्मीर के हालात पर 'द कश्मीर फाइल्स' अलग यह है कि यह फिल्म भारत के साम्प्रदायिक तत्वों को खुराक देती है।**

इस सत्यता से इंकार नहीं किया जा सकता कि पिछले आठ दस सालों में फिल्में भी राजनीति से प्रेरित होती जा रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य में 'पदमावती' फिल्म के दिखाए जाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने "केदारनाथ" को नहीं दिखाने दिया कि एक हिन्दू लड़की और एक मुस्लिम लड़के बीच प्यार की कहानी पर था। हिन्दू नफ़रत पसंदों की सरकार में तकलीफ से परेशान काल्पनिक भारत पर बनाई गई 'नेटफिलिक्स' की वेब सीरीज लिल्ली का सीजन-2 तो हिन्दू कट्टरवादियों के डर से प्रदर्शित ही नहीं किया जा सका था। कश्मीर के हालात पर 'द कश्मीर फाइल्स' अलग यह है कि यह फिल्म भारत के साम्प्रदायिक तत्वों को खुराक देती है।

अग्निहोत्री खुद कहते हैं कि उनकी प्राथमिकता कश्मीरी पंडित यानि हिन्दुओं से घृणा रखने वालों के रूप में दिखाया है इस फिल्म में जो नारेबाज़ी दिखाई गयी है वह अत्याधिक डराने वाली है। अग्निहोत्री ने राजनीति की तारीफ भी अपने पसंदीदा अंदाज़ में की इसमें फारूक अब्दुल्ला को खूब बदनाम किया गया है जबकि वह उस राज्य के मुख्यमंत्री के पद भी नहीं थे लेकिन उस समय की केन्द्रीय सरकार जो, उस समय के गर्वनर के ज़रिए राज्य पर सत्ता चला रही थी और जिसके

बाक़ी पेज 11 पर

इमरान ख़ान – क्रिकेट का सफल नायक पर राजनीति का विफल नायक

पाकिस्तान में बेशक सरकार बदल गई पर सत्ता की असली चाभी अब भी फौज के पास है। वर्ष 1992 के विश्व कप क्रिकेट के राष्ट्रीय नायक रहे इमरान ख़ान ने अपनी मौजूदा राजनीतिक पारी के आख़िरी ओवर में सिर की ऊंचाई से छह फीट ऊपर से ऐसी अवैध बाउसंर गेंदबाज़ी की, जो विपक्षी दलों – पीएमएल (एन०), पीपीपी और एमक्यूएम (पी.) के नेताओं को तो छू नहीं पाई लेकिन मैकियावेली शैली से उन्हें मात दे दी। यह किसी भी तरह से उनकी स्विंग यार्कर नहीं थी लेकिन उसने पाकिस्तान के संविधान का मखौल उड़ाया और उन्हें उन क्रिकेट कप्तानों की श्रेणी में ला दिया, जिन्होंने खेल के नियम तोड़कर अपनी गरिमा खो दी। 41 वर्ष पहले जब गेंद से छेड़छाड़ को कानूनी मान्यता थी, तब इमरान ख़ान का सामना करना आसान नहीं होता था। अब उन्होंने गेंद के साथ छेड़छाड़ की है (जब इसकी अनुमति नहीं है) और संसद में संख्या बल के खेल में हारने के बाद अपना अस्तित्व बचाने के लिए संयुक्त विपक्ष को क्लीन बोल्ड करने की कोशिश, जो नाकाम साबित हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस कृत्य को ख़ारिज करते हुए वहां की संसद को दोबारा बहाल करने का आदेश दिया।

पाकिस्तान के लोगों की उम्मीद मुल्क के सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी जिसने एक सही फैसला दिया। इससे पहले पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने यह स्पष्ट कर दिया कि नेशनल असेंबली को भंग करने के संबंध में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा दिए गए सभी आदेश और कार्य अदालत के फैसले के अधीन होंगे। मौजूदा सांविधानिक संकट में मुख्य न्यायाधीश की प्रतिक्रिया सर्वोपरि और प्रासंगिक रही। सुप्रीम कोर्ट मौजूदा परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा नेशनल असेंबली भंग किए जाने की वैधता की जांच करेगा।

इमरान ख़ान एक विभाजित व्यक्ति हैं, जिन्हें विरोधाभासों और असमानता के मिश्रण के रूप में वर्णित किया जा सकता है और जिनकी मैक्रियावेली शैली का अंदाज़ा सेना और विपक्ष को डराने के लिए अपनाई गई हालिया रणनीति से लगाया जा सकता है। लंदन में पढ़ाई के दौरान उन्हें प्लेबॉय के रूप में जाना जाता था, क्योंकि वह अक्सर सुपर मॉडल्स की संगत में रहते थे और विलासितापूर्ण जीवन जी रहे थे। 43 वर्ष की आय तक वह अविवाहित रहे और उसके बाद उन्होंने तीन शादियां कीं। अपने मुल्क के शीर्ष पद पहुंचने की उनकी यात्रा और सत्ता से चिपके रहने की उनकी बेताब पैंतरेबाज़ी सिनेमा की पटकथा से मिलती जुलती है, जो हमेशा सच्चाई और ज़मीनी हक़ीक़त से दूर होती है।

विडंबना देखिए कि कभी इमरान ख़ान को खेल भावना का अवतार माना जाता था और वह खेल की गरिमा की रक्षा के लिए हद से आगे चले जाते थे। उन्होंने 1989 में लाहौर में दो कट्टर प्रतिद्वंदियों भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहें एकदिवसीय मैच में के० श्रीकांत को वापस मैदान में बुला लिया था, जिन्हें वकार यूनिस की गेंद पर अंपायर ने ग़लत ढंग से एलबीडब्यू क़रार दिया था, जिससे पूरी दुनिया स्तब्ध थी। लेकिन उनकी गरिमा का पतन देखिए, अब हाल यह है कि अपने कथित 'आश्चर्यजनक कदम के कारण संविधान को अमान्य कर दिया।'

जब इमरान ने अमेरिकी साज़िश की बात की, तो उसे बाजवा ने यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि अमरिका के साथ पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते हैं। यह सेना और इमरान ख़ान के बीच दरार का सबूत था, जो सार्वजनिक हो गया। इमरान पाकिस्तान के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, जिन्होंने सेना को चुनौती देने का साहस किया, जिसने उनके पतन का मार्ग प्रशस्त किया।

ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे 69 वर्षीय पश्तूनी राजनेता ने 2021 में अविश्वास मत जीता था, जो तब उन्हें मंज़ूर था, लेकिन पिछले दिनों जब उनकी हार तय थी, तो उनकी मानसिकता बदल गई। उन्हें मात्र 142 सांसदों का समर्थन था, जबकि विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव ख़ारिज होने के बाद 342 सीटों वाली संसद में 199 सांसदों के साथ दुनिया के सामने अपनी शक्ति प्रदर्शित की थी, जिसमें सत्ताधारी दल के 24 दलबदलू सदस्य भी शामिल थे। इमरान का 'नया पाकिस्तान' का सपना तभी चकनाचूर हो गया था, जब उनकी सरकार गंभीर आर्थिक संकट से निपटने, आसमान छूती महंगाई, मुद्रास्फीति के उच्चतम स्तर, बिगड़ती कानून व्यवस्था और विदेश नीति जैसे सभी मोर्चा पर विफल साबित हुई थी। इमरान ख़ान की सरकार ने बढ़ती महंगाई और विशेष रूप से चीन से लिए गए कर्ज़ के कारण जनता का भी समर्थन खो दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि इमरान ने अपनी पराजय के लिए विदेश साज़िश (अमेरिका) जैसे कारक को दोषी बताकर देशवासियों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश की, जिसका उद्देश्य आगामी चुनावों के लिए ज़मीन तैयार करना था। अमेरिकी अधिकारियों ने इस दावे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे कल्पना की उपज बताया।

वर्ष 2018 के चुनाव जीतने में सेना ने उनकी पूरी मदद की थी, इसलिए विपक्ष ने हमेशा उन्हें सेना के हाथ की कठपुतली बताया। लेकिन सेना के साथ उनके संबंध तब बिगड़ गए, जब इमरान ने आईएसआई प्रमुख की नियुक्ति पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया, हालांकि बाद में उन्हें झुकना पड़ा, लेकिन इमरान और बाजवा के बीच खाई चौड़ी हो गई। दूसरी बात, जब इमरान ने अमेरिकी साज़िश की बात की, तो उसे बाजवा ने यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि अमरिका के साथ पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते हैं। यह सेना और इमरान ख़ान के बीच दरार का सबूत था, जो सार्वजनिक हो गया। इमरान पाकिस्तान के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, जिन्होंने सेना को चुनौती देने का साहस किया, जिसने उनके पतन का मार्ग प्रशस्त किया। तीसरी बात, बाजवा ने बहुत

बाक़ी पेज 11 पर

मामले घटे हैं पर ख़तरा टला नहीं, इसलिए मास्क पहनना बेहतर

सवाल:– महाराष्ट्र और दिल्ली ने मास्क पहनने की अनिवार्यता ख़त्म कर दी है, ऐसा करना ठीक है?

जवाब:– कोरोना संक्रमण के मामले घटे हैं और न्यूनतम स्तर पर है, पर एक विषाणु विज्ञानी के तौर पर मेरी निजी राय है कि हमें अपने सेफगार्ड कम नहीं करने चाहिए। यदि हम आज मास्क पहनना बंद करते हैं तो वह हमारे लिए उचित नहीं है। चीन, सिंगापुर समेत कई देशों में अभी भी संक्रमण के मामले ज़्यादा है। हमारे देश में भी रोज़ सैकड़ों में मामले अभी आ रहे हैं। जिस प्रकार से देश में आवाजाही है उससे एक कोने से दूसरे कोने में संक्रमण फैलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। कोरोना के विषाणु में कब क्या बदलाव हो जाए, यह कह नहीं सकते। इसलिए अभी मास्क पहनना ज़रूरी है।

सवाल:– एनआईवी वायरस पर शोध करने वाली सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, कितने वायरस, बैक्टीरिया आपकी प्रयोगशाला के भंडारगृह में हैं?

जवाब:– हज़ारों की तादाद में हैं संख्या का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि सिर्फ कोरोना के ही 350 से अधिक स्ट्रेन हमारे पास मौजूद हैं। कई ऐसे वायरस व उनके स्ट्रेन भी है जो अब दुनिया में मौजूद नहीं है वे सिर्फ हमारी लैब में हैं या दूसरी लैब्स में हैं।

सवाल:– लैब में वायरस या बैक्टीरिया को रखना कितना सुरक्षित है?

जवाब:– इन्हें बायो सेफ्टी लेवल-4 लैब में रखा जाता है। ये 100 प्रतिशत सुरक्षित हैं। इनके लीकेज होने की आशंका ज़रा भी नहीं है।

सवाल:– देश में ज़्यादातर लोगों का प्राइमरी टीकाकरण हो चुका है आपको लगता है कि अब सभी लोगों के लिए बूस्टर डोज ज़रूरी है?

जवाब:– बूस्टर डोज लगाने का काम चरणबद्ध तरीक़े से शुरू हो चुका है। एहतियाती खुराक पर दिशा निर्देश आएंगे। आने वाले दिनों में सब को बूस्टर डोज लगेगी।

सवाल:– 12 वर्ष के छोटे बच्चों को टीका लगना चाहिए?

जवाब:– बच्चों का प्रतिरोधक तंत्र संक्रमण का सामना आसानी से कर सकता है। ज़्यादातर बच्चों को संक्रमण हो चुका है तथा उनमें लक्षण नहीं या हल्के दिखे हैं जो बच्चे बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें टीका लगाया जाना चाहिए।

सवाल:– क्या अब वैक्सीन को अपग्रेड करने की योजना है?

जवाब:– हमने कोरोना के पांच और स्ट्रेन आइसोलेट करके हाल में भारत बायोटेक को सौंपे हैं यह हमारे लिए उनके बीच हुए समझौते के तहत है। अब वे इससे कोई नया टीका बनाएंगे या नहीं यह उनको तय करना है।

सवाल:– सरकार ने एनआईवी की नई प्रयोगशालाएं खोजने किया था, दिशा में क्या प्रगति हुई.?

जवाब:– एनआईवी की चार और प्रयोगशालाएं खुलेंगी। इसके लिए बजट मंज़ूर हो चुका है। योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। वे प्रयोगशालाएं चंडीगढ़, डिब्रूगढ़, जबलपुर तथा बेंगलूरु में खुलेंगी। इस प्रकार पांच एनआईवी कार्य करेंगे जो अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में होंगे ताकि आपात स्थिति में पूरे देश को कवर कर सकें। ❑❑

अब सरकारी स्कूल के बच्चे भी सीख सकेंगे जर्मन भाषा

सरकारी स्कूलों में छात्र अब जर्मन भाषा भी सीखेंगे। इसके लिए दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जर्मन दूतावास के सहयोग से ग़ैर लाभकारी जर्मन सांस्कृतिक एसोसिएशन गोएथे इंस्टीट्यूट मैक्स मूलर भवन के साथ एक एमओयू साइन किया है। उपमुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसौदिया ने भारत में जर्मन के राजदूत वाल्टर जे लिंडर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस भागीदारी का उद्देश्य दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को प्रोफेशनल रूप से तैयार करना है। शिक्षा निदेशक व डीबीएसई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन हिमांशु गुप्ता, एससीईआरटी के निदेशक रजनीश कुमार, शिक्षा निदेशक के प्रधान सलाहकार शैलेंद्र शर्मा व गोएथे इंस्टीट्यूट मैक्समुलर भवन के क्षेत्रीय रीजनरल डायरेक्टर (साउथ-एशिया) डॉ. बर्थहोल्ड फ्रेंक भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। सिसौदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को ग्लोबल एक्सपोजर देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों में शुरू किए गए विदेशी भाषा पाठयक्रम में से जर्मन वह भाषा है जिसे शुरूआती दौर में बच्चे सीखेंगे। उन्होंने कहा कि यह भागीदारी सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए नए रोज़गार के साथ साथ कई शैक्षणिक अवसर भी खोलेगी। भारत में जर्मन राजदूत वाल्टर जे लिंडन ने कहा कि दिल्ली सरकार के साथ यह पार्टनरशिप भविष्य के कल्चर म्यूज़िक एजुकेशन सहित कई नए क्षेत्रों में पार्टनरशिप के अवसर तैयार करेगी।

संपादकीय

शांति मिशन

रमज़ान इबादत का महीना है इसे गपशप में न गुज़ारें

रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है इस माह को क़ुरआन का महीना भी कहा गया है, इसलिये क़ुरआन आसमान से दुनिया पर इसी माह में नाज़िल किया गया था, क़ुरआन में कहा गया है कि रमज़ान वह महीना है जिसमें क़ुरआन नाज़िल किया गया है इससे साफ़ ज़ाहिर हो गया है कि क़ुरआन को रमज़ान से और रमज़ान का क़ुरआन से एक ख़ास सम्बन्ध है और दोनों को एक-दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। रमज़ान में रोज़ेदार मुसलमान हर तरह के गुनाह और बेकार बातों से बचने की पूरी-पूरी कोशिश करता है जबकि क़ुरआन को समझकर पढ़ने वाला बारह महीने गुनाहों से बचने की कोशिश करे इसलिये अगर बग़ौर जायज़ा लिया जाये तो यह बात समझ में आती है कि क्योंकि क़ुरआन को रमज़ान से एक ख़ास सम्बन्ध है इसलिये इसके अंदर वही खूबी है जो रमज़ान के रोज़े और इसकी दीगर इबादात के अंदर है इसलिये मुसलमानों को यह जान लेना चाहिये कि अल्लाह को इनसे केवल रमज़ान में ही नहीं बल्कि ग़ैर रमज़ान में भी वही औसाफ़ मतलूब है।

इस्लाम की बेशतर तालीमात व इबादात का असल मक़सद इत्तहादुल बैनुल मुसलीमीन है इसी के साथ इस्लाम की बेशतर शिक्षायें इंसानी ख़िदमात का भी अहाता करती है लेकिन आश्चर्य की बात है कि कुछ तबक़ात इबादत के असल उद्देश्य को छोड़कर खुराफात में मुब्तला हो जाते हैं। रोज़ा में भूखा-प्यासा रहकर एक तरफ जहां हर तरह के गुनाह के काम से बचना होता है वहीं रोज़े की हालत में इंसान को दूसरे भूखे प्यासे आदमी के दर्द का अंदाज़ा हो जाता है रोज़े का यही असल मक़सद और संदेश है। रोज़ा सिर्फ भूखे-प्यासे मुसलमानों के ही दर्द का अंदाज़ा नहीं कराता बल्कि यकसां तौर पर वह ग़ैर मुस्लिम भूखे-प्यासे लोगों के साथ भी हमदर्दी करना सिखाता है। आमतौर पर इंसानों में जो बुराईयां पाई जाती हैं रोज़ा इनसे भी रोक दे लेकिन देखने में यह आया है कि नौजवान रोज़े का सही इस्तेमाल नहीं करते और वक्तगुज़ारी के लिये अजीब-गरीब रास्ते तलाश करते हैं।

आमतौर पर यही होता है कि रोज़ा रखने वाले नौजवान काम की रफ्तार सुस्त कर देते हैं परंतु इस बचे हुये समय का कोई जायत इस्तेमाल नहीं करते अकसर यह होता है कि सेहरी के बाद सो जाते हैं और फज्र की नमाज़ जमाज के साथ न अदा करके रोज़े की क्या अहमियत रह जाती है। इसके बाद सोकर उठते हैं नमाज़ फज्र अदा की, फिर गपशप में लग गये जुहर की नमाज़ के बाद कुछ तो क़ुरआन की तिलावत में मसरुफ़ हो जाते हैं परंतु अकसर मस्जिदों में बैठकर दुनियावी बातों में व्यस्त हो जाते हैं अगर ये लोग खामोशी के साथ महज़ अल्लाह के नाम का ही विर्द करे तो कितना सवाब कमायें लेकिन दुनियावी बातों में मशग़ूल रहकर रोज़े के तक़दुस के साथ-साथ मस्जिद के भी तक़दुस को पामाल करते हैं। इबादत तो नौजवानी की अफ़ज़ल है। लोग अक्सर समझते हैं कि इबादत तो बड़े-बूढ़े लोग करते हैं परंतु इस्लाम ने नौजवानी की इबादत को ही अफज़ल क़रार दिया है कि नौजवानों को बहुत से दुनियावी और पेशेवाराना काम होते हैं इसके बावजूद वह वक्त निकाल कर इबादत करते हैं तो अल्लाह के नज़दीक इसका महत्व ज़्यादा होता है इसलिये बेहतर है कि अपने रोज़ाना के काम भी करे तथा जो समय बचे इसको गपशप में न गुज़ारे बल्कि इबादत करें।

रोज़े में मेहनत का अहसास ही तो कराया जाता है अगर इस अहसास से बचने के रास्ते तलाश कर लिये जायें और काम में भी कमी ले आई जाये तो रोज़े का मक़सद ही फ़ौत हो जाता है। हाँ, ताक़त से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिये इसकी इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी है। परंतु जान-बूझकर रोज़े की लज़्ज़त से वंचित रह जाना समझदारी नहीं। रोज़ा रखना किसी पर एहसान करना नहीं है इसलिये रोज़ा रखकर काम में हददर्जे कमी लाना उचित नहीं है परंतु मुस्लिम मालिकों को खुद इसका ख़्याल रखना चाहिये कि वे रोज़ेदार कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करे और आम दिनों के मुक़ाबले में इनसे कम काम ले। इस माह की ख़ास इबादत रोज़ा, तरावीह के बाद तिलावत क़ुरआन पाक है, क़ुरआन पाक की तिलावत करते समय इस बात का ख़्याल रखे कि क़ुरआन को तर्जुमे के साथ समझ कर पढ़ें अल्लाह ने सारे दीनी तथा दुनियावी मसाएल का हल क़ुरआन में रख दिया है।

रमज़ान में मस्जिदों के लाउडस्पीकर कुछ ज़्यादा ही एक्टीव हो जाते हैं, इस तरफ संजीदगी के साथ विचार करना चाहिये। रमज़ान में समय का परिवर्तन हमारा अपना है और हमारे लिये है इसमें दूसरे वर्गों को शामिल करना इन पर ज़्यादती करना है मिसाल के तौर पर हम सेहरी के लिये सुबह को मामूल के हिसाब से ज़रा जल्दी उठते हैं इसलिये अकसर मस्जिदों में माईक पर नात ख़्वानी और विभिन्न तरह के ऐलान होते रहते हैं। ख़ालिस मुस्लिम आबादियां बहुत कम हैं। शहरों में तो अक्सर मुश्तरक आबादी वाले मुहल्ले होते हैं इन मुहल्लों में जब मस्जिद से माइक पर बेतरतीब ऐलान होते हैं तो बिरादराने वतन को ही कष्ट होता है अक्सर बिरादराने वतन देर से सोने के आदी होते हैं जब हम तीन बजे माइक पर शोर-मचाना शुरू करते हैं तो इनके आराम में ख़लल पड़ता है, हमें इससे बचना चाहिये इस्लाम किसी को कष्ट पहुंचाने नहीं आया परंतु इस उसूल को हमें व्यवहारिक रूप से करके भी दिखाना चाहिये आजकल तो आधुनिक टेक्नोलॉजी ने हर मैदान में अपना लोहा मनवा लिया है हर हाथ पर घड़ी है और लगभग हर घर में मोबाईल है दोनों चीज़ों में अलार्म लगे हुए हैं अलार्म इस वक्त तक बोलता रहता है जब तक आप जाग न जाए अत: इस पहलू पर हम सबको ध्यान देना चाहिए।

क़ुरआन की बात से मज़मून की इब्तदा हुई थी तो यहां इस का ज़िक्र ज़रूरी है कि क़ुरआन वाहिद किताब है जिसकी हिफ़ाज़त का ज़िम्मा खुद अल्लाह ने लिया है। क़ुरआन पर रफीक़ हमले कोई नई बात नहीं। खुद हिन्दुस्तान में ऐसे बदनसीब मौजूद हैं जो क़ुरआन पर हमले कर चुके हैं लेकिन इनका क्या हश्र हुआ सबके सामने है। एक बदबख़्त चौपड़ा ने 80 की दहाई में क़ुरआन पर पाबंदी के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में रिट दायर की थी लेकिन अल्लाह ने इसकी रूसवायी का ऐसा इंतज़ाम कराया कि इसकी गुमराह करने वाली दलीलों के बावजूद अदालत ने याचिका को ख़ारिज किया ही खुद उसको भी फटकार लगाई। फेस बुक पर ऐसे कई दृश्य पड़े हुए हैं जिनमें क़ुरआन को हाथ में लेकर नाऊज़ुबिल्लाह नज़रें आतिश करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को यह ईमान रखना चाहिए कि क़ुरआन के तक़दुस को इन्शाअल्लाह ता-क़यामत कोई ज़क नहीं पहुंचा सकेगा जो ऐसा करने की कोशिश करेगा। इन्शाअल्लाह उसका अंजाम इस दुनिया में भी बुरा होगा और आखिरत में तो उसके मुक़द्दर में अबदी ज़िल्लत है ही इस सिलसिले में मुसलमानों से एक बात अर्ज़ करनी है कि ऐसे मरदूद वाक़यात पर इज़हारे नाराज़गी ज़रूरी है लेकिन एक हद तक। उसके बाद मामला अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। मुसलमानों के करने का काम यह है कि हर घराना अपने एक बच्चे को ज़रूर हाफिज़-ए-क़ुरआन बनाए।□□

6

हज़रत उमर रज़ि॰ का फौजी निज़ाम

कि जंग के महकमे की ये वसअत जिसमें तमाम क़ौमों को दाख़िल कर लिया गया था, सिर्फ इस्लाम की एक फ़ैयाज़ी थी वरना फतूहाते मुलकी के लिये अरब को अपनी तलवार के सिवा किसी का भी ममनून होना नहीं पड़ा, अलबत्ता इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता कि जिन क़ौमों से मुक़ाबला था उन्हीं की हम क़ौमों को इनसे लड़ाना फने जंगे का बड़ा उसूल था।

जैसाकि हम ऊपर लिख आये हैं कि इब्तिदाये इस्लाम में फौजी विभाग साफ साफ जुदागाना हैसिअत नहीं रखता था यानि जो लोग और हैसिअत से तंख्वाह पाते थे उनके नाम भी फौजी रजिस्टर में दर्ज थे और इस वक्त यही मसलहत थी, हज़रत उमर ने अब ये पर्दा भी उठा देना चाहा, शुरू शुरू में तंख्वाह की कमीबेशी में क़ुरआन खानी के वस्फ़ का लिहाज़ भी रखा जाता था लेकिन क्योंकि इसको फौजी मामलों से कोई सम्बन्ध न था, हज़रत उमर ने इसको शिक्षा विभाग से जोड़कर इसका दफतर अलग कर दिया।

तनख्वाहों में तरक्क़ी

इसके बाद तनख्वाहों की तरक्क़ी की तरफ तवज्जो की क्योंकि वह फौज को ज़राअत, तिजारत और इस तरह के सभी कामों से बजोर बाज़ू रखते थे इसलिये ज़रूरी था कि इनकी सारी ज़रूरियात की किफालत की जाये इस लिहाज़ से तनख्वाहों में काफी इज़ाफ़ा किया गया, अदना से अदना शरह जो 200 सालाना थी 300 कर दी गई अफसरों की तंख्वाह सात हजार से लेकर दस हजार तक बढ़ा दी। बच्चों का वज़ीफ़ा दूध छोड़ने के दिन से मुक़र्रर किया जाता था, अब हुक्म दे दिया गया कि पैदा होने के दिन से ही मुक़र्रर कर दिया जाये।

रसद का इंतज़ाम

रसद का बंदोबस्त पहले सिर्फ इस क़दर था कि फौजें मसलन कादसिया पहुंची तो आसपास के देहात पर हमला करके जिन्स व ग़ल्ला लूट लाये, अलबत्ता गोश्त का प्रबंध राजनधानी से था यानि हज़रत उमर रज़ि॰ मदीना मुनव्वरा से भेजा करते थे, फिर ये इंतज़ाम हुआ कि मफतूहा क़ौमों से जज़्ये के साथ फीकस 25 आसार ग़ल्ला लिया जाता था और वह रसद के काम आता था, मिस्र में ग़ल्ले के साथ ज़ैतून का तेल, शहद और सिरका भी वसूल किया जाता था जो सिपाहियों के सालन का काम भी करता था, जज़ीरे में भी यही निज़ाम था लेकिन इसमें रिआया को कष्ट होता था अत: हज़रत उमर ने आख़िर इसके बजाये नक़दी मुक़र्रर कर दी जिसको रिआया ने खुशी से क़बूल कर लिया।

रसद का मुस्तक़िल महकमा

रफ्ता-रफ्ता हज़रत उमर रज़ि॰ ने रसद का मुस्तक़िल प्रबंध किया जिसका नाम अहरा था चुनांचे शाम में उमर बिन उतबा इस महमके के अफसर नियुक्त हुये, अहरा हरी की जमा है हरी एक यूनानी लफज़ है जिसके मानी गोदाम के है, चूंकि रसद यकजा जमा होने और वहां से तकसीम होने का तरीक़ा यूनानियों से लिया गया था, इसलिये नामे में वही यूनानी शब्द शामिल रहा, सारी जिंस और ग़लला एक बड़े गोदाम में जमा होता था और महीने की पहली तारीख़ को फी सिपाही एक न असार के हिसाब से बांटा जाता था इसके साथ ही प्रति व्यक्ति 02 असार रोगन जैतून और दो असार सिरका भी मिलता था, इसके बाद और भी तरक्क़ी हुई, यानि खुश्क़ जिन्स के बजाये पका पकाया खाना दिया जाता था चुनांचे मवार्रिख़ याक़ूब ने हज़रत उमर रज़ि॰ के सफर शाम के ज़िक्र में इसकी तसरीह की है। (जारी)

खुराक, कपड़ा और भत्ता

तंख्वाह और खुराक के अलावा कपड़ा भी दरबारे ख़िलाफ़त से मिलता था जिसकी तफसील करही के ज़िक्र में आयेगी इन तमाम बातों के साथ-साथ भत्ता भी मुक़र्रर था जिसको अरब में मऊता कहते हैं, सवारी का घोड़ा संवारों को अपने अहतमाम से तैयार करना होता था, लेकिन जो आदमी ग़रीब होता था और इसकी तंख्वाह भी कम होती थी उसको घोड़ा सरकार की तरफ से मिलता था चुनांचे खास इस गर्ज के लिये हज़रत उमर रज़ि॰ के हुक्म से खुद राजधानी में चार हज़ार घोड़े हर वक्त मौजूद रहते थे।

चार बार मुख्यमंत्री रह चुकीं मायावती से उनके वोटरों ने बेरुख़ी क्यों इख़्तियार कर ली?

चन्द्रशेखर आज़ाद

05 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद जिस एक खास बात की सबसे ज़्यादा चर्चा है, वह है अनुसूचित जाति वर्ग के वोटिंग पैटर्न में बदलाव की। ख़ासतौर पर यूपी में उसके भाजपा के साथ जाने की बात हो रही है, जिसकी वजह से बीएसपी जहां एक सीट पर ठहर गई, वहीं भाजपा मुश्किल हालात में लगातार दूसरी बार सत्ता में पहुंचने में सफल हो गइ। अब भाजपा के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई आसान कही जाने लगी है। भीम आर्मी चीफ चन्द्रशेखर आज़ाद से संबंध में उनकी राय जानने की कोशिश की गई, पेश है चन्द्रशेखर जी से इन तमाम सवालों के जवाब :-

प्रश्नः- उत्तर प्रदेश में बीएसपी के कोर वोट के भाजपा में शिफ्ट होने की बात कही जा रही है। दिख भी रही है कि बीएसपी केवल एक सीट जीत पाई। क्या वजह देखते हैं?

उत्तरः- यह सोचने का विषय बहन मायावती का है जिस वर्ग ने उन्हें राजनीतिक ताक़त दी, जिसकी वजह से वह देश के सबसे बड़े राज्य की चार बार मुख्यमंत्री हुईं, उस वर्ग ने अचानक उनसे बेरुख़ी क्यों इख़्तियार कर ली? कोई न कोई वजह तो होगी ही। रही बात, उसके भाजपा में शिफ्ट होने की तो मैं इस तथ्य को स्वीकार नहीं करता हूं। मेरा मानना है कि बीएसपी से अनुसूचित जाति वर्ग का जो वोट शिफ्ट हुआ, उसका बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी को गया है।

प्रश्नः- माना तो यह भी जा रहा है कि 'लाभार्थी' के रूप में जो नया वोट बैंक तैयार हुआ, उसमें बड़ा

> **बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर के संविधान पर अगर किसी वर्ग को सबसे ज़्यादा भरोसा है तो अनुसूचित जाति वर्ग को ही है। जो भाजपा बाबा साहेब के संविधान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा हो, वह उसे कैसे वोट कर सकता है। यह प्रचारित होने पर कि यूपी की लड़ाई एसपी और भाजपा के बीच है तो संविधान बचाने के लिए उसके पास भी एसपी के साथ जाने के सिवाय और विकल्प नहीं था।**

हिस्सा अनुसूचित जाति का वर्ग का ही है। 'लाभार्थी' वोट बैंक भाजपा को गया। एसपी को जाता तो उसकी सरकार नहीं बन जाती?

उत्तरः-यह भाजपा का सुनियोजित प्रचार है कि उसे बीएसपी का वोट शिफ्ट हुआ है। 2017 के चुनाव में बीएसपी को करीब 22 प्रतिशत वोट मिला था, इस बार उसे 12 प्रतिशत ही मिला। दस प्रतिशत की शिफ्टिंग दिख रही है। भाजपा को 2017 के चुनाव में 39 प्रतिशत वोट मिला था। अगर भाजपा का वोट उसके साथ गया होता तो यह 49 प्रतिशत हो जाना चाहिए था लेकिन उसके वोट प्रतिशत में सिर्फ दो प्रतिशत की ही वृद्धि हुई, उधर समाजवादी पार्टी वोट में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं यह वोट किसका है? अपर कास्ट का वोट समाजवादी पार्टी को मिला नहीं। यह अनुसूचित वर्ग का ही वोट है।

प्रश्नः- अनुसूचित जाति वर्ग के समाजवादी पार्टी के साथ जाने की संभावना कम रहती है। 2019 के लोकसभा के चुनाव में गठबंधन के बावजूद एसपी को बीएसपी का कोर वोट नहीं मिल पाया था..?

उत्तरः- बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर के संविधान पर अगर किसी वर्ग को सबसे ज़्यादा भरोसा है तो अनुसूचित जाति वर्ग को ही है। जो भाजपा बाबा साहेब के संविधान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा हो, वह उसे कैसे वोट कर सकता है। यह प्रचारित होने पर कि यूपी की लड़ाई एसपी और भाजपा के बीच है तो संविधान बचाने के लिए उसके पास भी एसपी के साथ जाने के सिवाय और विकल्प नहीं था।

प्रश्नः- बीएसपी चीफ में इस बार पहले जैसा जोश दिखा ही नहीं, क्या वजह रही इसकी?

उत्तरः- उनके भीतर क्या चल रहा था, यह वह ही बता सकती हैं

प्रश्नः- अनुसूचित जाति वर्ग के एक नए हीरो के रूप में आपका उदय हुआ, लेकिन चुनाव में अनुसूचित वर्ग का भरोसा आप नहीं जीत पाए। क्या वजह देखते हैं?

उत्तरः- मैं किसी अनुसूचित जाति बहुल सीट से चुनाव लड़ने चला जाता तो आराम से विधायक हो जाता, लेकिन मैंने सामान्य सीट को चुना और वह भी मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़। किसी नेता ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई। मैंने चुनाव नहीं जीता लेकिन दुनिया को दिखा दिया कि अनुसूचित वर्ग के इस बेटे में बड़ी से बड़ी राजनीतिक शख़्सियत से टकराने की हिम्मत है। जहां तक पार्टी की बात है, यह हमारा पहला चुनाव था। भाजपा ने पूरा चुनाव जिस तरह से मैनेज कर रखा था, उससे पार पाना आसान नहीं था। अनुभव मिला, आगे के चुनाव में इसका असर दिखेगा।

प्रश्नः- पंजाब में अनुसूचित जाति वर्ग से सीएम बनाकर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ? खुद चन्नी भी दोनों जगह से हार गए

उत्तरः- अनुसूचित वर्ग ने अरग वहां कांग्रेस का समर्थन नहीं किया होता तो कांग्रेस की और बुरी स्थिति होती पंजाब में। रही बात चन्नी के हाराने की तो उनका आंतरिक कलह तो ज़िम्मेदार रही ही, साथ ही जातीय

> **मैंने सामान्य सीट को चुना और वह भी मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़। किसी नेता ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई। मैंने चुनाव नहीं जीता लेकिन दुनिया को दिखा दिया कि अनुसूचित वर्ग के इस बेटे में बड़ी से बड़ी राजनीतिक शख़्सियत से टकराने की हिम्मत है। जहां तक पार्टी की बात है, यह हमारा पहला चुनाव था। भाजपा ने पूरा चुनाव जिस तरह से मैनेज कर रखा था, उससे पार पाना आसान नहीं था।**

मानसिकता भी। तमाम जातियों को यह बात रास नहीं आ रही थी कि अनुसूचित जाति वर्ग का कोई सीएम हो।

प्रश्नः- 2024 का क्या भविष्य देखते हैं?

उत्तरः- इतना तय है कि भाजपा की धर्म की आंधी सुविधा की राजनीति से नहीं रोका जा सकता। अगर पार्टियां यह सोचती हैं कि चुनाव से तीन माह पहले सक्रिय होकर भाजपा को हरा देंगी तो यह गलत है। भाजपा को हराने के लिए 24X7 की प्रतिबद्धता चाहिए। भाजपा जो ज़हर बो रही है उसको उसी वक़्त बेअसर करना होगा।

प्रश्नः- क्या कांग्रेस, अखिलेश ओर मायावती को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे.?

उत्तरः- जो प्रयास करने थे, वे सब मैंने कर लिए। अब अकेले चलने की ठान ली है। अपने काडर को मज़बूत करूंगा, उसके ज़रिए बहुजन समाज को गोलबंद करूंगा। मेरा कारवां अब रुकने वाला नहीं है। ❏❏

सैद्धांतिक स्तर पर मैं जबरन केन्द्रीकरण की धारणा के ही ख़िलाफ़ हूं

तमिलनाडू के वित्त मंत्री डॉ. पलानिवेल त्यागराजन मानते हैं कि अगर विकास ग़रीबों में भी सबसे गरीब की ज़िन्दगियों तक पहुंचने में नाकाम रहे तो जीडीपी के आंकड़ों का ख़ास मतलब नहीं रह जाता, पेश है वैश्विक वित्तीय बाज़ारों के विश्लेषक रह चुके वित्त मंत्री के साथ एक साक्षात्कार के प्रमुख अंशः-

प्रश्नः- आपके मुख्यमंत्री तमिलनाडू को एक खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं..?

उत्तरः- एक लक्ष्य होना अच्छी बात है क्योंकि यह आपको जवाबदेह बनाता है। तीन वर्ष में एक खरब डॉलर की अर्थ व्यवस्था बनने के लिए हमें सामान्य तौर पर 14-14.5 फीसद दर हासिल करने की ज़रूरत है जिसमें महंगाई भी शामिल है। महंगाई फिलहाल 6.5 प्रतिशत के आसपास है, अगर मैं इसे निकाल दूं तो इसका मतलब है कि मुझे करीब 7.5-8 फीसद की विकास दर चाहिए, जिसे हासिल करना मुश्किल नहीं है।

प्रश्नः- तमिलनाडू ने औद्योगिक राज्य बनने की कोशिश करते हुए भी हमेशा कल्याणकारी राज्य होने में यकीन किया है। आप बही-खातों में संतुलन कैसे लाते हैं?

उत्तरः- यह धारणा ही बुनियादी तौर पर ग़लत है कि कल्याणकारी राज्य पूंजीवादी या औद्योगिकतावादी राज्य नहीं हो सकता। दुनिया भर में कल्याणकारी समाज आर्थिक भेदभाव कम करने और समावेशी होने, सर्वश्रेष्ठ अर्थ व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप भारत को लें, तो तमिलनाडू इन सब चीज़ों पर किसी से भी ज़्यादा ख़र्च कर सकता है और मानव तथा सामाजिक विकास संकेतकों, हाई स्कूलों/कॉलेजों में सकल नामांकन अनुपात वगैरह में उसके नतीजे प्रथम राज्यों में से एक है। आप जितने ज़्यादा कल्याणकारी और परवाह करने वाले होंगे..आपके यहां उत्पादकता और वृद्धि भी उतनी ही ज़्यादा होगी इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है।

प्रश्नः- आपके श्वेतपत्र ने संसाधनों में केन्द्र के घटते योगदान की ओर उंगली उठाई। यह रिश्ता अब ग़ैर बराबरी के किस स्तर पर खड़ा है?

उत्तरः- सैद्धांतिक स्तर पर मैं जबरन केन्द्रीकरण की धारणा के ही ख़िलाफ़ हूं। पर अभी मान लें कि यह मौजूं नहीं हैं अमल के स्तर पर दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए एक क़िस्म की योजना बनाना मूर्खतापूर्ण है। स्वच्छ भारत की मिसाल लें। उन्होंने कहा कि हमने टॉयलेट बनाए, कोई परेशानी नहीं। वे कहते हैं कि हम सीधे स्थानीय निकाय के पास जाएंगे, उन्हें पैसा देंगे और वे टॉयलेट बनाएंगे। सीएजी की रिपोर्ट में कई गड़बड़ियां दिखाई गई हैं कोई परेशानी नहीं। मगर सबसे बड़ी

> **यह धारणा ही बुनियादी तौर पर ग़लत है कि कल्याणकारी राज्य पूंजीवादी या औद्योगिकतावादी राज्य नहीं हो सकता। दुनिया भर में कल्याणकारी समाज आर्थिक भेदभाव कम करने और समावेशी होने, सर्वश्रेष्ठ अर्थ व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं।**

परेशानी यह है कि आप जब टॉयलेट बना देते हैं तो पानी सप्लाई कौन करेगा? केन्द्र तो नहीं करेगा, बराबर? पंचायत या निगम करेगा। आप हरेक पंचायत की जलापूर्ति दिल्ली से नहीं संभाल सकते, बराबर? यह फैसला स्थानीय लोगों को करना चाहिए।

प्रश्नः- तमिलनाडू को दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य माना जाता है, मगर 2011 से राष्ट्रीय स्तर पर आपकी रैंकिंग गिर रही है..?

उत्तरः- इन चीज़ों को आप कैसे आंकते हैं? फिलहाल तमिलनाडू की प्रति व्यक्ति आय लगभग 10,000-15,000 रुपए है, जो गुजरात से कम है लेकिन तमिलनाडू में 15 वर्ष से छोटी एक भी लड़की ऐसी नहीं जो स्कूल में न हो। गुजरात में उनमें से 15-20 प्रतिशत स्कूल में नहीं हैं किस किस्म का विकास मैं चाहता हूं? तमिलनाडू में हर 1000 लोगों पर चार डॉक्टर है, गुजरात में हर हजार लोगों पर एक डॉक्टर है। किस किस्म का समाज मैं चाहता हूं। जीडीपी के आंकड़े ही सब कुछ नहीं हैं हमारी ज़िन्दगी जीने का तरीका है जिसकी मैं रक्षा करना और बनाए रखना चाहता हूं, जिसे मुख्यमंत्री प्रविडियन मॉल कहते हैं। हम इसे लागू करेंगे और बीते 10 वर्ष में जो भी कमियां रहीं हैं, अगले पांच साल में हम फिर शीर्ष पर लौटेंगे। मुझे 100 प्रतिशत यकीन है।

मिज़ान .... शंकर अय्यर

रूस पर प्रतिबंध कितने कारगर?

त्रासदियां कार्रवाई से शुरू होती हैं और अक्सर न उठाए जाने वाले क़दमों के कारण और भी भीषण हो जाती हैं। अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के प्रतिबंधों ने रूस को विचलित नहीं किया है। कीव की घेरा की जा रही है कॉमेडियन और अभिनेता से नेता बना ब्लादिमीर जेलेंस्की रूस की ताक़त के सामने खड़ा है और दुनिया द्वारा असहाय छोड़ दिए गए लोग बचने के लिए पड़ोसी देश पोलैंड में शरण ले रहे हैं या आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए पेट्रोल बम बना रहे हैं। जमीनी धरातल पर प्रतिबंधों के ब्यौरे और वास्तविकता में अंतर देखने लायक़ हे। पिछले दिनों अमेरिकी सरकार ने रूस पर 'गंभीर प्रतिबंधों' की पहली कड़ी की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की कि उनका उद्देश्य ब्लादिमीर पुतिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खारिज करना है। उनकी इस घोषणा के एक घंटे के भीतर कच्चे तेल की कीमत प्रतिबंध से पूर्व के स्तर से नीचे गिर गई। शेयर बाजार गहरे लाल रंग से चमकीले हरे रंग के क्षेत्र में चले गए। शेयरों में वृद्धि यही बताती है कि रूस को मिला दंड पर्याप्त नहीं है।

एक दिन बाद यूरोपीय संघ ने नए प्रतिबंधों की घोषणा की। रूसी संस्थाओं के वित्तीय प्रवाह को बंद करने, विमान के पुर्ज़ों और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तक पहुंच पर प्रतिबंध लगाने के अलावा यूरोपीय संघ के प्रतिबंध पुतिन और रूसी विदेश मंत्री की सम्पत्ति फ्रीज करना चाहते हैं। कोई नहीं जानता कि उनके पास रूस से बाहर संपत्ति है या नहीं। सच यही है कि प्रतिबंध बेलारूस के एलेक्जेंडर लुकाशेंकों और सीरिया के बशर अल असद को भी तानाशाही तौर तरीक़ों से नहीं रोक पाए।

रूस पर प्रतिबंधों को लेकर यूरोपीय संघ के भीतर जो तथाकथित सर्वसम्मति बनी, उसमें भी सब एकमत नहीं थे। व्यापक रूप से माना गया कि रूस को वैश्विक वित्तीय प्रणाली स्विफ्ट (सोसायटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन) बैंकिंग प्रणाली से बाहर करना कठिन है। ब्रिटेन स्विफ्ट से रूस को बाहर करना चाहता था। अमेरिका ने इस पर हिचकिचाहट दिखाई, जबकि जर्मनी और हंगरी ने इस प्रस्ताव को ख़ारिज कर दिया। आख़िरकार यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों एवं साझेदारों ने स्विफ्ट से चुनिंदा रूसी बैंकों को अलग करने और रूस के केन्द्रीय बैंक के ख़िलाफ़ प्रतिबंधात्मक क़दम उठाने का फैसला किया है। इटली ने विलासिता की इतालवी वस्तुओं को प्रतिबंध के दायरे से बाहर निकाला और बेल्जियम के हीरे के व्यापार को प्रतिबंध पैकेज से बाहर निकाला और बेल्जियम के हीरे के व्यापार पर प्रतिबंध पैकेज से बाहर रखने के लिए कड़ा संघर्ष किया। यूरोपीय दोहरापन साफ है – रूसी कुलीन वर्गों के लिए विलासिता की महंगी वस्तुओं को खरीद पाने की आज़ादी आक्रमण झेल रहे एक संप्रभु राष्ट्र के लोगों की स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है।

ज़ाहिर है कि यूक्रेन से आने वाली तस्वीरों को देख यूरोप ने यह महसूस किया कि नाटो सहयोगियों में से किसी भी देश का यह हश्र हो सकता है, लिहाज़ा पुतिन की आक्रामकता को यूक्रेन की सीमाओं पर नहीं रोका जा सकता। यूरोप में

रूस पर प्रतिबंधों को लेकर यूरोपीय संघ के भीतर जो तथाकथित सर्वसम्मति बनी, उसमें भी सब एकमत नहीं थे। व्यापक रूप से माना गया कि रूस को वैश्विक वित्तीय प्रणाली स्विफ्ट (सोसायटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन) बैंकिंग प्रणाली से बाहर करना कठिन है।

रूस के बहुपक्षीय व्यापार और सुरक्षा व्यवस्था को ख़तम कर ही पुतिन को सबक़ सिखाया जा सकता है। क्या अमेरिका और उसके सहयोगी देश पुतिन को रोक पाएंगे.?

प्रतिबंध सैद्धांतिक रूप से काम कर सकते हैं, पर इतिहास बताता है कि इसका असर सबसे धीमी है। जब रूस ने क्रीमीया पर कब्ज़ा किया था, तब अमेरिका और उसके सहयोगियों ने उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। तब रूस ने अपने लोक वित्त को डॉलर से अलग किया, अब रूस पर जीडीपी अनुपात में सबसे कम कर्ज़ है और उसका भंडार 650 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। साथ ही, उसने सीरिया में असद के शासन को बनाए रखा है, क्रीमीया पर रूस का कब्ज़ा बना हुआ है और अब यूक्रेन के सामने 'असैन्यीकरण' का ख़तरा है।

चीन ने इस प्रतिबंधों को 'अप्रभावी' बनाकर ख़ारिज कर दिया। इसकी वजह है – 1989 में तियानमेन चौराहे के विरोध के बाद यूरोपीय संघ और अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाए थे। उनका उद्देश्य चीन को ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाना था। पर उसके बाद बीजिंग ने हांगकांग में लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया, भारत के साथ वह अकारण सीमा युद्ध छेड़े हुए हैं, और ताइवान पर कब्ज़ा करने की महत्वकांक्षा उसने जताई है। ऐसे में, अमेरिकी अधिकारियों ने चीन से यूक्रेन में युद्ध रोकने की जो गुहार लगाई है उसे विडंबना ही कहेंगे। यूरोपीय संघ के 10 सदस्य ऊर्जा के लिए रूस पर निर्भर हैं। अगर रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्ज़ा करने के समय जर्मनी ने रूस से अपने ऊर्जा समझौते की समीक्षा की होती, तो क्या आज वह रूस पर इतना निर्भर होता? क्या यूरोप अपने ऊर्जा ग्रिड को आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार नहीं कर सकता था? द *वर्ल्ड फॉर सेल* के लेखक जेवियर ब्लास कहते हैं, 'जब से लड़ाई शुरू हुई, रूस की गैस की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है।'

दशकों से अमेरिका और उसके सहयोगियों ने अपनी ऐच्छिक सोच को ही रणनीति के रूप में पेश किया है। अमेरिका और नाटो सहयोगियों को उम्मीद थी कि शीतयुद्ध रूस शांतिपूर्ण और समृद्ध यूरोप के विचारों को आत्मसात करेगा। ऐसे ही निक्सन प्रशासन ने चीन से दोस्ती में निवेश किया। फिर उनकी सरकार ने इस उम्मीद में विश्व व्यापार संगठन में चीन के प्रवेश का समर्थन किया कि एक दिन मुख्यधारा के लोकतंत्रों में शामिल हो जाएगा।

जो प्रश्न पश्चिम और नियम आधारित विश्व व्यवस्था को परेशान करना चाहिए, वह यह कि जब चीन जिनपिंग के अनुसार ताइवान को फिर से अपने साथ जोड़ने की ओर बढ़ता है, तब उसके पास क्या विकल्प हैं? तब क्या अमेरिका और उसके सहयोगी प्रतिबंधों को निवारक के रूप में देख सकते हैं? जिस प्रश्न का उत्तर तलाशा जाना चाहिए, वह यह है कि क्या संयुक्त राष्ट्र अपने मौजूदा ढांचे में संप्रभुता और नियम आधारित विश्व व्यवस्था को संरक्षित कर पाता है? क्या पश्चिम सुरक्षा परिषद के और अधिक प्रतिनिधित्वशाली होने पर सहमत हो सकता है? कहा जाता है कि दशकों तक कुछ नहीं होता और फिर कुछ ही सप्ताहों में दशकों का काम हो जाता है। इतिहास का अंत इतिहास की शुरूआत भी है। ◻◻

रोज़गार ....

हैल्थ सेफ्टी एंड एंवायरनमेंट के क्षेत्र में कैरियर

उत्तर भारत के ज़्यादातर बड़े शहरों में स्मॉग यानि कि ज़हरीला धुआं लोगों की समस्या बना हुआ है। दिल्ली/एनसीआर इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है। हालात इतने ख़राब हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक को दख़ल करना पड़ जाता है। राज्य सरकारों से लेकर केन्द्र सरकार इस मामले में उलझी हुई है।

यह सारा मामला हैल्थ सेफ्टी और एंवायरमेंट से जुड़ा है। मनुष्य निर्मित परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से इस तरह की समस्या खड़ी होती है लेकिन ऐसी आपदाओं से निपटने के क्षेत्र में भी कैरियर की अपार संभावनाएं हैं और यह संभव है हेल्थ सेफ्टी एंड एंवायरमेंट से जुड़े कोर्स करने से। इसमें काफी स्कोप है।

माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में प्रशिक्षित और अनुभवी युवाओं की मांग और बढ़ेगी। अत: जो लोग इस क्षेत्र में कैरियर की बुलंद तक पहुंचना चाहते हैं वे डिप्लोमा से लेकर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सो के ज़रिए आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि स्मॉग जेसी समस्या भी एक दो दिन की समस्या नहीं है, बल्कि यह अब नियमित समस्या बनती जा रही है, ऐसे में इससे निपटने के लिए ज़रूरी प्रयास करने की ज़रूरत है। इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत इस क्षेत्र में हेल्थ सेफ्टी एंड एंवारनमेंट में प्रशिक्षित लोगों की मांग तेज़ी से बढ़ने की संभावना है।

कैसे-कैसे कोर्स

इस क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए विभिन्न संस्थानों द्वारा कई तरह के कोर्स कराए जा रहे हैं। हैल्थ सेफ्टी एंड एंवारनमेंट से जुड़े लोगों को आमतौर पर सामान्य सेवाओं से जुड़ा हुआ मान लिया जाता है। लेकिन खास बात यह है कि यह कोर्स करने के बाद औद्योगिक क्षेत्र में ऐसे प्रशिक्षित युवाओं की मांग ज़्यादा है।

ट्रेड डिप्लोमा इन हैल्थ सेफ्टी एंड एंवायरनमेंट का कोर्स करने के लिए अभ्यर्थी का 12वीं या उसके समकक्ष पास होना अनिवार्य है। यह कोर्स 18 माह होता है। इसके साथ ही फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट कोर्स भी किया जा सकता है। हालांकि फायरमैन, सब ऑफिसर, असिस्टेंट डिवीजनल ऑफिसर, डिवीजनल ऑफिसर जैसे पदों के लिए अलग-अलग कोर्स किए जा सकते हैं।

कार्य का स्वरूप

हेल्थ सेफ्टी एंड एंवायरनमेंट इंजीनियर का मुख्य काम आपदा या दुर्घटना के कारणों का पता लगाना, उसकी रोकथाम और वायु प्रदूषण एवं अन्य तरह के प्रदूषण के कारणों को रोकना होता है।

शैक्षणिक योग्यता

हेल्थ सेफ्टी एंड एंवारनमेंट विशेषज्ञ के अंदर साहस और धैर्य के साथ लीडरशिप क्वालिटी और क्विक डिसीजन लेने की क्षमता का होना ज़रूरी है ताकि किसी भी बड़ी दुर्घटना को कंट्रोल कर सके।

फिर भी डिप्लोमा या डिग्री में दाख़िले के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसमें प्रवेश के लिए ऑल इंडिया इंट्रेंस एक्ज़ाम होता है। कैमिस्ट्री के साथ फिजिक्स या गणित विषय में 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

शारीरिक योग्यता

शैक्षणिक योग्यता के साथ इस क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए शारीरिक पात्रता भी अहमियत रखती है। पुरुषों के लिए न्यूनतम लंबाई 165 सेंटीमीटर, वजन 50 किलोग्राम वहीं महिलाएं कम से कम 157 सेंटीमीटर लंबी हों, वजन कम से कम 46 कि.ग्रा. होना ज़रूरी है। आई विजन दोनों के लिए 6/6 होनी चाहिए। और उम्र 19 से 23 वर्ष के अंदर होना चाहिए।

प्रमुख संस्थान

दिल्ली कॉलेज आफ फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग, नई दिल्ली

www.dcse.com

इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।

www.ignue.com

इंटरनेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ सिक्यूरिटी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, पुणे महाराष्ट्र www.iism.com

इंस्टीच्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड फायर सेफ्टी, मोहाली पंजाब। ◻◻

इस्लामी दुनिया

जहाज़ से टकराकर नौका पलटी, 06 मरे

ढाका : बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बाहरी इलाके में शीतलक्ष्य नदी में एक नौका के मालवाहक जहाज से टकरा जाने के कारण कम से कम छह लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि सैयदपुर अल अमीन नगर इलाके में एमवी अफसर उद्दीन नामक नौका की एमवी रूपोशी-9 नामक जहाज से टक्कर हो गयी। नौका में कम से कम 50 यात्री सवार थे। इस हादसे के बाद नौका डूब गई। दुर्घटना के बाद बांग्लादेश अंतरर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण ने नदी पुलिस, नौसेना तटरक्षक बल के साथ मिलकर इलाके में बचाव अभियान शुरू कर दिया है।

पाकिस्तान के सियालकोट मिलिट बेस पर धमाके

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के उत्तरी शहर सियालकोट में बीते दिनों एक के बाद एक कई धमाके हुए। मीडिया में रिपोर्ट्स के अनुसार धमाके की आवाज़ें इतनी तेज़ थी कि इसे पंजाब प्रांत में छावनी क्षेत्र के पास तक सुना गया। बताया गया है कि यह एक गोला बारूद स्टोरेज एरिया है। धमाके के बाद एक बड़ी आग जलती हुई देखी गई। कुछ स्थानीय मीडिया रिपोर्ट की मानें तो पाकिस्तानी सेना ने इस घटना पर अपना आधिकारिक बयान में कहा कि मिसाइल पी.एल.-15 के परीक्षण के दौरान यह हादसा हुआ।

पाकिस्तान में शहबाज़ विपक्षी प्रत्याशी

कराची: अविश्वास प्रस्ताव के चलते पाक पीएम इमरान ख़ान की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। विपक्ष का दावा है कि इमरान ने अपना बहुमत खो दिया है और इसीलिए बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट और सेना के चक्कर काट रहे हैं। इस बीच विपक्ष ने शहबाज़ शरीफ़ को अपनी तरफ से पाकिस्तान के पीएम का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। यदि 28 मार्च को इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उनकी जगह पूर्व पीएम नवाज़ शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज़ शरीफ देश के नए पीएम बन सकते हैं।

राजनीतिक दलों की घेरेबंदी में इमरान

इस्लामाबाद : विपक्षी दलों की घेराबंदी के कारण पद जाने की अशंका से घिरे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने इस्लामिक देशों के 57 सदस्यीय संगठन (ओआईसी) के मंच से कश्मीर का राग अलापकर फिर ध्यान भटकाने की कोशिश की है। सम्मेलन में चीन के विदेशमंत्री वांग यी भी मौजूद थे, लेकिन चीन में उइगर मुसलमानों के दमन पर चुप ही रहे। उन्होंने मुस्लिम एकजुटता का आहवान करते हुए कहा, 'हम डेढ़ अरब मुसलमान हैं, पर कश्मीर और फलस्तीन का मुद्दा सुलझाने में असफल रहे हैं।

प्रमोद भार्गव

जातिविहीन भारत की कल्पना

पांच राज्यों में चुनावी माहौल अपने पूरे चरम पर है। हर पार्टी अपने पक्ष में लोगों को अधिक संख्या में करने का हरबा इस्तेमाल करती है और वह है जातिवाद में बांटकर एक ही झटके में वोट प्राप्त करने का फंडा। बड़े नेता सिर्फ बातों में जातिवाद के ख़िलाफ़ बोलते हैं असल में वो हर उस जाति को अपने पक्ष में रखना चाहते हैं जिसके वोट से उन्हें सत्ता प्राप्त हो सकती है, उसके लिए वह कुछ भी करते हैं। हाल में केरल के शिवगिरी मठ में एक समारोह में उपराष्ट्रपति वेकैंया नायडु ने भारत में जाति व्यवस्था को खत्म कर जाति विहीन एवं वर्ग विहीन व्यवस्था की उम्मीद जताई थी। उन्होंने मंदिरों, गिरजाघरों और मस्जिद के प्रमुखों से जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने यह बात तब कही है जब दुनिया 'वसुधैव कटुंबकम' की धारणा से विमुख होकर अस्तित्ववाद की ओर बढ़ रही है। अस्तित्ववाद अमेरिका और ब्रिटेन से लेकर भारत तक में प्रखर राष्ट्रवाद के रूप में सामने आ रहा है जबकि आर्थिक उदारवाद के परिप्रेक्ष्य में यह धारणा बनी थी कि दुनिया में व्यापार के माध्यम से विश्व ग्राम की स्थापना होगी, जो भारत की सांस्कृतिक परंपरा वसुधैव कुटुंबकम का ही पर्याय है। भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को शिक्षा एवं सरकारी नौकरी में ऐसे संवैधानिक प्रावधान कर दिए गए हैं, जिनके चलते क़तई नहीं लगता कि निकट भविष्य में जातीय कुचक्र टूटेगा।

बृहत्तर हिन्दू समाज (हिन्दू, जैन, बौद्ध, सिख) में जिस जातीय संरचना की ब्राह्मणवादी व्यवस्था का दुश्चक्र माना जाता है, हक़ीक़त में इस जातीय व्यवस्था की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसकी तह में जा पाना मुश्किल है। मुस्लिम समाज में भी जातिप्रथा पर पर्दा डला हुआ है। अभिजात्य मुस्लिम वर्ग यही स्थिति बनाए रखना चाहता है, जबकि मुसलमानों में सौ से अधिक जातियां हैं परंतु इनकी जनगणना में भी पहचान का आधार धर्म और लिंग है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि जाति ब्राह्मणवादी व्यवस्था का कुछ ऐसा दुष्चक्र है कि हर जाति को अपनी जाति से छोटी जाति मिल जाती है। यह ब्राह्मणवाद नहीं है, बल्कि पूरा एक चक्र है। अगर जाति चक्र एक सीधी रेखा में होता तो इसे तोड़ा जा सकता था। यह वर्तुलाकार हैं इसका कोई अंत नहीं है। जब इससे मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। वैसे भी धर्म के बीच संस्कार जिस तरह से हमारे बाल अवचेतन में, जन्मजात संस्कारों के रूप में बो दिए जाते हैं, कमोबेश उसी स्थिति में जातीय संस्कार भी नादान उम्र में उड़ेल दिए जाते हैं।

इस तथ्य को एकाएक नहीं नकारा जा सकता कि जाति एक चक्र है। यदि जाति चक्र न होती तो अब तक टूट गई होती। जाति पर ज़बरदस्त कुठाराघात महाभारत काल के भौतिकवादी ऋषि चार्वाक ने किया था। गौतम बुद्ध ने भी भगवान के नाम से चलाई जाने वाली उस राजसत्ता को धर्म से पृथक किया। धर्म, जाति और वर्णाश्रित राज व्यवस्था को तोड़ कर बुद्ध समग्र भारतीय नागरिक समाज के लिए समान आचार संहिता प्रयोग में लाए। चाणक्य ने जन्म और जातिगत श्रेष्ठता को तिलांजलि देते हुए व्यक्तिगत योग्यता को मान्यता दी है। गुरुनानक देव ने जातीय अवधारणा को अमान्य करते हुए राजसत्ता में धर्म के उपयोग को मानवाधिकारों का हनन माना। संत कबीरदास ने जातिवाद को ठेंगा दिखाते हुए कहा था कि '*जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान।*' महात्मा गांधी के जाति प्रथा तोड़ने के प्रयास तो इतने अतुलनीय थे कि उन्होंने 'अछूतोद्धार' जैसे आंदोलन चला कर सफाईकर्मी का काम दिनचर्या में शामिल कर, उसे आचरण में आत्मसात किया। भगवान महावीर, संत रैदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, संत ज्योतिबा फुले, डॉ. आंबेडकर ने जाति तोड़क अनेक प्रयत्न किए, लेकिन जाति मज़बूत होती चली गई।

इतने सार्थक प्रयासों के बाद भी क्या जाति टूट पाई? नहीं, क्योंकि कुलीन हिन्दू मानसिकता, जाति तोड़क कोशिशों के समानांतर अवचेतन में पैठ जमाए बैठे मूल से अपनी जातीय अस्मिता और उसके भेद को लेकर लगातार संघर्ष करती रही हैं इसी मूल की प्रतिच्छाया हम पिछड़ों और दलितों में देख सकते हैं। मुख्यधारा में आने के बाद न पिछड़ा, पिछड़ा रह जाता है और न दलित, दलित। वह उन्हीं ब्राह्मणवादी हथकंडों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगता है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के हज़ारों साल हथकंडे रहे हैं। नतीजतन जातीय संगठन और राजनीतिक दल भी अस्तित्व में आ गए।

जातिगत आरक्षण के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद-16 की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन आरक्षण किसी भी जाति के समग्र उत्थान का मूल कभी नहीं बन सकता, क्योंकि आरक्षण के सामाजिक सरोकार केवल संसाधनों के बंटवारे और उपलब्ध अवसरों में भागीदारी से जुड़े हैं। इस आरक्षण की मांग शिक्षित बेरोज़गारों को रोज़गार और अब ग्रामीण अकुशल बेरोज़गारी के लिए सरकारी योजनाओं में हिस्सेदारी से जुड़ गई है। परंतु जब तक सरकार समावेशी आर्थिक नीतियों को अमल में लाकर आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों तक नहीं पहुंचती, तब तक पिछड़ी या निम्न जाति अथवा आय के स्तर पर पिछले छोर पर बैठे व्यक्ति के जीवनस्तर में सुधार नहीं आ सकता। लेकिन यहां प्रश्न यह उठता है कि पूंजीवाद की पोषक सरकारें समावेशी आर्थिक विकास की पक्षधर क्यों होंगी?

जातिगत आरक्षण के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद-16 की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन आरक्षण किसी भी जाति के समग्र उत्थान का मूल कभी नहीं बन सकता, क्योंकि आरक्षण के सामाजिक सरोकार केवल संसाधनों के बंटवारे और उपलब्ध अवसरों में भागीदारी से जुड़े हैं। इस आरक्षण की मांग शिक्षित बेरोज़गारों को रोज़गार और अब ग्रामीण अकुशल बेरोज़गारी के लिए सरकारी योजनाओं में हिस्सेदारी से जुड़ गई है। परंतु जब तक सरकार समावेशी आर्थिक नीतियों को अमल में लाकर आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों तक नहीं पहुंचती, तब तक पिछड़ी या निम्न जाति अथवा आय के स्तर पर पिछले छोर पर बैठे व्यक्ति के जीवनस्तर में सुधार नहीं आ सकता। लेकिन यहां प्रश्न यह उठता है कि पूंजीवाद की पोषक सरकारें आर्थिक विकास की पक्षधर क्यों होंगी?

इस्लाम में जाति प्रथा की कोई गुंजाइश नहीं है। जबकि मुसलमान भी चार श्रेणियों में विभाजित है। उच्च वर्ग में सैयद, शेख, पठान, अब्दुल्ला, मिर्ज़ा, मुग़ल, अशरफ जातियां शुमार हैं। पिछड़े वर्ग में कुंजड़ा, जुलाहा, धुनिया, दर्जी, रंगरेज, डफाली, नाई, पमारिया आदि शामिल हैं। पठारी क्षेत्रों में रहने वाले मुस्लिम आदिवासी जनजातियों की श्रेणी में आते हैं। अनुसूचित जातियों के समतुल्य धोबी, नट, बंजारा, बक्खो, हलालखोर, कलंदर, मदारी, डोम, मेहतर, मोची, पासी, खटीक, जोगी, फकीद आदि हैं। मुस्लिमों में ये ऐसी प्रमुख जातियां हैं जो पूरे देश में लगभग इन्हीं नामों से जानी जाती है। इसके अलावा देश के राज्यों में ऐसी कई जातियां हैं जो क्षेत्रीयता के दायरे में हैं। जैसे बंगाल में मंडल, विश्वास, चौधरी, राएन, हलदर, सिकदर आदि। यही जातियां बंगाल में मुस्लिमों में बहुसंख्यक हैं। इसी तरह दक्षिण भारत में मरक्का, राऊथर, लब्बई, मालाबारी, पुस्लर, बोरेवाल, गारदीय, बहना, छप्परबंद आदि। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर आदि में विभिन्न उपजातियों के क्षेत्रीय मुसलमान हैं। राजस्थान में सरहदी, फीलबान, बक्सेवाले आदि हैं। गुजरात में संगतराश, छीपा जैसी अनेक नामों से जानी जाने वाली बिरादरियां हैं। जम्मू कश्मीर में ढोलकवाल, गुडवाल, बकरवाल, गोरखन, वेदा (मून) मरासी, डुबडुबा, हैगी आदि जातियां है। इसी प्रकार पंजाब में राइनों और खटीकों की भरमार है।

इतनी प्रत्यक्ष जातियों होने के बावजूद मुसलमानों को लेकर यह भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि ये जातियां दुष्चक्र में नही जकड़े हैं। दरअसल जाति विच्छेद पर आवरण कुलीन विभिन्न मुस्लिम जातियों को एक सूत्र में बांधना क़तई नहीं है। गोया, ये इस छद्म आवरण की ओट में सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं पर एकाधिकार रखना चाहते हैं, जिससे इनका और इनकी पीढ़ियों को लाभ मिलता रहे। सन 1931 में हुई जनगणना में बिहार और ओडिसा में मुसलमानों की तीन बिरादरियों का ज़िक्र है - मुसिलम डोम, मुस्लिम हलालखोर और मुस्लिम जुलाहे। बाकी जातियों को किस राजनीति के तहत हटाया गया, इसकी पड़ताल हो तो अच्छा है। यदि ऐसा होता है तो वास्तविक रूप से आर्थिक बदहाली झेल रही जातियों को सरकारी लाभ योजनाओं से जोड़ा जा सकेगा।

अल्पसंख्यक समूहों में इस वक्त हमारे देश में पारसियों की घटती जनसंख्या चिंता का कारण हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के एक सर्वे के मुताबिक पारसियों की जनसंख्या 1941 में 1,1400 के मुकाबले 2001 में केवल 69000 रह गई। इस समुदाय में ज्यादा आयु में विवाह की प्रवृत्ति के चलते भी यह स्थिति बना है। इस जाति का देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इस जाति को सुरक्षित रखने की दृष्टि से ही नागरिकता संशोधन विधेयक लाया गया, उसमें उन्हें भारत में ही रहने के प्रावधान किए गए है। बहरहाल ऐसे समाज या धर्म सम्प्रदाय को खोजना मुश्किल है, जो जातिय कुचक्र के चक्रव्यूह में जकड़ा न हो? ❑❑

वाई. के. गोयल

यौन अपराध संकट में पड़ते बच्चे

हाल में दिल्ली पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने बाल यौन शोषण सामग्री के ख़िलाफ़ बड़ा अभियान 'ऑपरेशन मासूम' चला कर छत्तीस घंटे के भीतर 95 लोगों को गिरफ्तार किया। इससे यह पता चलता है कि बच्चों के यौन शोषण और अश्लील सामग्री का धंधा किस तेज़ी से पैर पसार चुका है। गूगल के अलावा वाट्सऐप्प, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर भी बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री की भरमार समाज और सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई हैं। ज़ाहिर है, बच्चों के ख़िलाफ़ होने वाले अपराध तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) से मिली सूचनाओं के आधार पर की थी। एनसीआरबी का एनसीएमईसी (नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लाइटेड चिल्ड्रन) नामक एक संगठन के साथ क़रार है, जो सोशल मीडिया पर बारीकी से नज़र रखता है और बच्चों के यौन शोषण व अश्लील गतिविधियों को चिह्नित कर आइपी (इंटरनेट प्रोटोकॉल) पते की मदद से संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचता है और एनसीआरबी को इसकी सूचना देता है। एनसीआरबी इसकी सूचना पुलिस को देता है, ताकि अपराधियों तक पहुंचा जा सके।

आज दुनिया का शायद ही कोई देश होगा जो बाल यौन शोषण की समस्या से ग्रस्त न हो। इसलिए यह समस्या वैश्विक स्तर पर भी गंभीर चिंता का विषय बन गई है। बच्चों के प्रति बढ़ते यौन अपराधों को लेकर संयुक्त राष्ट्र तक में आवाज़ें उठती रही हैं। पर दुख की बात यह है कि इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिए जाने की वजह से यह बुराई फैलती ही जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक़ भारत में पिछले वर्ष पूर्णबंदी लागू होने के बाद से बाल अश्लील सामग्री का ऑनलाइन मांग में ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली। दिसंबर 2019 के दौरान इंटरनेट पर अश्लील सामग्री की मांग सौ शहरों में औसतन 50 लाख प्रतिमाह थी, लेकिन पूर्णबंदी के बाद इसका उपभोग 95 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गया।

न्यूयार्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष इंटरनेट पर बाल यौन शोषण से संबंधित करीब दो करोड़ मामले सामने आए। इसके शिकार पीड़ित बच्चों में हालांकि लड़के और लड़कियां दोनों ही हैं, लेकिन इनमें लड़कियों का अनुपात काफी ज़्यादा होता है। इंटरपोल के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2017 से 2020 के बीच तीन सालों में ऑनलाइन बाल यौन शोषण के चौबीस लाख से ज़्यादा मामले सामने आए थे, जिनमें से अस्सी प्रतिशत पीड़ित चौदह साल से कम आयु की लड़कियां थीं। हालांकि बाल यौन शोषण से निपटने में इंटरपोल काफी सक्रिय है। पिछले कुछ माह में इंटरनेपाल और इंटरनेट वॉच फाउंडेशन की मदद स केन्द्र सरकार को बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री वाली साढे तीन हज़ार से भी अधिक वेबसाइटों को बंद करने में सफलता मिली थी, लेकिन इसके बावजूद इंटरपोल के डाटा से स्पष्ट है कि ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री और उसके ग्राहक तेज़ी से बढ़ रहे हैं।

एनसीआरबी के मुताबिक वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में यौन उत्पीड़न को चित्रित करने वाली सामग्री के प्रकाशन एवं प्रसारण में करीब पांच गुना वृद्धि हुई। बाल शोषण के मामले भी तेज़ी से बढ़े हैं। नासूर बनती इस समस्या के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से कुछ ही दिनों पहले सीबीआई ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा सहित राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 77 स्थानों पर छापेमारी करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया था। दरअसल जांच में देशभर में ऐसे 70 से अधिक शहरों की पहचान हुई थी, जहां से बाल यौन शोषण कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा था। सीबीआई जांच के दायरे में पचास से भी ज़्यादा ऐसे इंटरनेट मीडिया समूह थे, जिनमें पांच हज़ार से भी अधिक अपराधी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नाइजीरिया, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, यमन, मिस्र आदि कई देशों में स्थित आरोपियों के साथ बाल शोषण सामग्री साझा कर रहे थे। इनमें से कई समूहों में विदेशी नागरिकों की भी संलिप्तता भी सामने आई और इनमें कम से कम सौ देशों के लोगों के शामिल होने का अंदेशा है

सोशल मीडिया या अन्य किसी माध्यम से साझा की गई अश्लील सामग्री के आधार पर इसे साझा करने वालों को भुगतान किया जाता है, ताकि ऐसी सामग्री को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट मीडिया समूहों में साझा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके और बड़े पैमाने पर इसका प्रसार हो सके। इसलिए इस धंधे में लगे लोगों को पकड़ना और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी के लिए कम चुनौतीभरा नहीं है हालांकि ऐसे अपराधों से निपटने के लिए संबंधित एजेंसियों ने साफ्टवेयर बनाए हैं जो किसी भी इंटरनेट साइट पर बाल अश्लीलता से संबंधित कोई फोटो या वीडियो अपलोड होते ही उससे जुड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं और संबंधित एजेंसियां फोटो तथा वीडियो साइट देख कर पता लगा लेती हैं कि वे किस मोबाईल या लैपटाप से इंटरनेट पर डाले गए है।

बात यौन शोषण व अश्लील सामग्री मामलों में अपराध साबित हो जाने पर कम से कम पांच वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। साथ ही दोषियों पर लाखों रुपए का जुर्माना भी किया जा सकता है, लेकिन आरोपी प्रायः कानूनी दांव-पेंच से बच निकलते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 की धारा 67 के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अपराध घोषित करते हुए पहली बार यह अपराध करने के लिए पांच वर्ष का कारावास और दस लाख रुपए जुर्माना और उसके बाद भी अपराध करने पर 06 वर्ष कारावास और 10 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया था। पाक्सो, अधिनियम (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) में भी बाल अश्लीलता के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। इस अधिनियम में बच्चों के यौन अंगों के चित्रण, वास्तविक अथवा नक़ली यौन गतिविधियों में बच्चे की भागीदारी और बच्चे के अभद्र या अनुचित चित्रण सहित किसी भी प्रकार के उपयोग को अपराध माना गया है।

दरअसल अश्लील सामग्री के उपभोग की प्रवृत्ति बच्चों के प्रति बढ़ते अपराधों के एक बड़े कारण के रूप में सामने आई है। ऐसी सामग्री देखने और खरीदने वाले लोग ज़्यादातर मामलों में मासूम बच्चों के साथ यौनाचार जैसे मामलों में लिप्त पाए गए हैं। इसके लिए गरीब परिवारों के बच्चों की खरीद फरोख़्त होती है। बाल यौन शोषण का दायरा केवल बलात्कार अथवा गंभीर यौन आघात तक ही नहीं सिमटा है, बल्कि बच्चों को इरादतन यौनिक कृत्य दिखाना, ग़लत इरादे से छूना, अनुचित कामुक बातें करना, जबरन यौन कृत्य भी बाल अश्लीलता और यौन शोषण के दायरे में आते हैं। चूंकि बच्चे इन कृत्यों का प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं होते इसलिए वे इन अनैतिक कृत्यों में लिप्त अपराधियों के लिए बहुत आसानी से निशाना बन जाते हैं। बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार के ख़िलाफ़ देश में 2012 में पारित यौन अपराध के ख़िलाफ़ बच्चों के संरक्षण क़ानून सहित व्यापक कानूनी ढांचा है और ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का भी प्रावधान है, लेकिन तकनीकी चूक, कार्यान्वयन में अनियमितता तथा त्वरित कार्रवाई नहीं होने के कारण ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। बहरहाल, बच्चे चूंकि किसी भी राष्ट्र के विकास और उत्थान की नींव होते हैं और इस नींव की मज़बूती के लिए बेहद ज़रूरी है कि बाल यौन शोषण जैसी नासूर बनती समस्या के उन्मूलन के लिए बेहद कठोर क़दम उठाए जाएं।□□

> **अश्लील सामग्री के उपभोग की प्रवृत्ति बच्चों के प्रति बढ़ते अपराधों के एक बड़े कारण के रूप में सामने आई है। ऐसी सामग्री देखने और खरीदने वाले लोग ज़्यादातर मामलों में मासूम बच्चों के साथ यौनाचार जैसे मामलों में लिप्त पाए गए हैं। इसके लिए गरीब परिवारों के बच्चों की खरीद फरोख़्त होती है। बाल यौन शोषण का दायरा केवल बलात्कार अथवा गंभीर यौन आघात तक ही नहीं सिमटा है, बल्कि बच्चों को इरादतन यौनिक कृत्य दिखाना, ग़लत इरादे से छूना, अनुचित कामुक बातें करना, जबरन यौन कृत्य भी बाल अश्लीलता और यौन शोषण के दायरे में आते हैं।**

ख़ास ख़बरें

चीन में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान का एक ब्लैक बॉक्स मिला

वुझोउ : चीन में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के दो 'ब्लैक बॉक्स' में से एक मिल गया है। राहतकर्मियों को यह जानकारी दी। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की ख़बर के अनुसार चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के यात्री विमान का एक ब्लैक बॉक्स मिल गया है। चाइना इस्टर्न एयरलाइंस के यून्नान ब्रांच के चेयरमैन सुन शियिंग ने सम्मेलन में बताया था कि दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में सवार 132 लोगों में से कोई अभी तक जीवित नहीं मिला है।

मॉस्को पर विश्वास नहीं कर सकते : जेलेंस्की

कीव : यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ जारी वार्ता में कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं, लेकिन मॉस्को पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वहीं, क्रेमलिन ने कहा कि यूक्रेन के साथ वार्ता में कोई सफलता नहीं मिली है। जेलेंस्की ने वीडियो संबोधन में कहा, इस्तांबुल को मॉस्को की प्रतिक्रिया ठीक थी और वार्ता आगे बढ़ने की उम्मीद है।

दलित युवक को मंदिर में नाक रगड़ने को किया मजबूर

जयपुर : राजस्थान के अलवर जिले में एक दलित युवक को कुछ लोगों ने मंदिर में कथित रूप से नाक रगड़ने को मजबूर किया तथा उससे मारपीट भी की। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार पीड़ित युवक राजेश कुमार मेघवाल एक निजी बैंक में काम करता है। आरोप है कि सोशल मीडिया पर फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' की आलोचना संबंधी अपनी एक टिप्पणी के जवाब में उसने हिन्दू देवताओं के लिए कथित तौर पर अपमाजनक टिप्पणी लिखी थी, जिससे नाराज़ कुछ लोगों ने उससे मारपीट की और उसे मंदिर में नाक रगड़ने को मजबूर किया तथा माफ़ी मांगने को कहा।

विषाक्त टॉफी खाने से चार बच्चों की मौत

कुशीनगर : उत्तर प्रदेश में कुशीनगर के कसया क्षेत्र में कथित रूप से विषाक्त टॉफी खाने से एक ही परिवार के तीन मासूमों सहित चार बच्चों की मौत हो गई। उपजिलाधिकारी वरुण कुमार पांडेय ने ग्रामीणों के हवाले से बताया कि कसया थाना क्षेत्र के कुड़वा उर्फ दिलीप नगर के लठउर टोला की मुखिया देवी सुबह घर के दरवाज़े पर झाड़ू लगा रही थीं। इसी दौरान उन्हें एक पॉलिथिन में पांच टॉफी और नौ रुपए मिले। उन्होंने उसमें से तीन टॉफी अपने नातियों और एक टॉफी पड़ोसी के बच्चों को दे दी।

फरीज़ा-ए-रमज़ान की हिकमतें

हज॰ मौलाना सै॰ अबुल हसन अली नदवी (रह॰)

''ऐ इमान वालों! तुम पर रोज़े फर्ज़ किए गए हैं जैसे तुम से पहलो पर किए गए थे ताकि शायद तुम में तक़्वा पैदा हो। (सूरह बकरा)

इस्लाम अपने पीरों को जिस एतदाल, ज़ब्त नफ्स, इताअत और रूहानियत के कमाल तक पहुंचाना चाहता है उसके लिए उसने दो रास्ते अख़्तियार किए हैं।

जो चीजें और आमाल इंसान की ज़िन्दगी में खुद फरामोशी सख़्त बेअतदाली, मअसीयत और इरतकाब जुर्म की तरफ तबई मिलान पस्ती और बेअमली की तरफ रूझान और सरकशी की रगबत दुनिया की ज़िन्दगी की बढ़ी हुई हविस, तईश व फस्क़ फजूर का बोहरान बेयाई और बेग़ैरती की तरगीब पैदा करते हैं, इन सब को उसने अबदी तौर पर इंसान के लिए ममनूअ क़रार दे दिया, जिस में उम्र के किसी मरहले और ज़माने के किसी इख़्तलाफ़ और देश व मकाम के किसी इम्तियाज़ को दख़ल नहीं है, ममनूआत की इस सूचि में वह सारी मआसी दाख़िल है, जो कभी इंसान के लिए हलाल और जाइज़ नहीं उदाहरणार्थ, शराब, लहम खंज़ीर कमार, रबवा, माल हराम और दूसरे मआसी।

जब कोई व्यक्ति इस्लाम क़बूल करता है या मुसलमान सन बलूग को पहुंचता है तो वह इन सारी चीज़ों से रोज़ा रख लेता है। इस रोजे़ की इब्तिदा या इस ज़िन्दगी की सुबह सादिक़, इस्लाम के अहकाम का मुखातिब बन जाता है। अब इस रोजे़ का अफ्तार उम्र के सूरज के डूबने से पहले नहीं है, यह एक लम्बा रोज़ा है जो हर मुसलमान को सफ़र व हिज्र में रखना होता है और हालत इज़्तरार (शरई) के सिवा कोई असतश्ना नहीं। शरीअत के उद्देश्यों को पाने के लिए और इन मआसी को बन्द करने के लिए जिनका ऊपर ज़िक्र किया गया है यह रोज़ा लाज़मी है।

इन मन्सूस चीज़ों के अलावा लज़्ज़त की सारी चीजें (बशर्ते कि वह हुरमत व कराहत से ख़ाली हों) मुबाह और जाइज़ हैं इन से ख्वाह-म-ख्वाह के लिए रुकना पसंदीदा निगाह से नहीं देखा गया है और इन हलाल चीज़ों को अपने लिए हराम कर लेना शरीअत में एक तरह की तहरीफ, दीन में हिंसा और कुफ़्राने नेमत क़रार दिया गया है। ''आप कह दीजिए कि किस ने हराम किया है अल्लाह की इस ज़ीनत और पवित्र रिज़्क़ को जो उसने अपने बन्दों के लिए निकाला है, आप कह दीजिए कि यह सब चीजें ईमान वालों के लिए दुनिया में भी हैं और आख़िरत में तो मख़्सूस तौर पर। (सूरह आराफ)

दूसरी आयत में फरमाया गया है कि खाना-पीना नाजायज़ नहीं बल्कि असराफ नाजायज़ है। ''बस खाओ और पियो और असराफ मत करो। (सूरह अल आराफ)

लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं कि इन मुबाहात व लज़ायज़ का बेक़ैद और दायमी इस्तेमाल, लज़्ज़तों में इन्हमाक अक़्ल व शरब की दायमी आज़ादी, इस जादा-ए-एतदाल से इंसान को हटा देती है जिस पर दीन मुसलमान को देखना चाहता है, इसके रुझानात और जिन्दगी के उद्देश्यों को बदल देती है और बाज़ औक़ात नफ़्स परवरी, शिक्म परवरी नाव नोश और बईश कोश मकसूद ज़िन्दगी बन जाता है।

तबिअत में एक तरह की बिलादत और बेहिसी पैदा हो जाती है। ज़ब्त नफ्स और जफ़ाकशी की कुवत बाक़ी नहीं रहती, तन आसानी, तन्अम की खू पैदा हो जाती है। इंसानियत की रूह कुचल जाती है और रूहानी जज़्बात मुर्दा हो जाते हैं। सालों साल और बाज़ औक़ात पूरी उम्र, हक़ीक़ी रूहानी मुसर्रत सबक़ रूही, दिमाग़ की यक्सूई, ज़िक्र व इबादत में लज़्ज़त, मुनाज़ात की हलावत नसीब नहीं होती, बाअज़ लोगों को सालों ख़ाली पेट होने और एतदाल की सआदत हासिल नहीं होती और वह इसका मज़ा नहीं जानते।

इस एअतदाल, ज़ब्ते नफ्स और रूहानियत की कुव्वत को बढ़ाने के लिए दो रास्ते थे एक तक्लील तआम का रास्ता था लेकिन इसमें दो नुक़्स हैं एक तो उसका उमूमी मैयार, सब के लिए एक मिक्दार निर्धारित करना अत्याधिक मुश्किल है और इसको लोगों की राय और तमीज़ पर छोड़ना भी दुश्वार, कि अव्वल तो यह उसूल तशरीह (आईनसाज़ी) के ख़िलाफ़ हैं, दूसरे धर्म अख़्लाक़ की तारीख़ में इसका तजुर्बा हमेशा नाकाम रहा है, लोगों ने इस आज़ादी और अख़्तयार का हमेशा ग़लत इस्तेमाल किया है और मुब्हलम और ग़ैर मुईन अहकाम अमलन बेकार व बेनतीजा होकर रह गए (जैसे बहुत से अख़्लाक़ी निसाह और हिदायात) दूसरे अक्सर सिर्फ तक्लील-ए-तआम सी तबाअ के लिए बिल्कुल ग़ैर मोअसर और बेनतीजा तदबीर है।

दूसरा रास्ता यह है कि कोई ऐसा तवील वक़्फ़ा मुक़र्रर किया जाए जिसमें कोई चीज़ इस्तेमाल न हो, यह तरीक़ा ज़्यादा हंसी, ज़्यादा मोशर और कुव्वते बहीमिया को अधिक कमज़ोर करने वाला है यह वक़्फहा दीन की इस्तलाह में 'सोम' या रोज़ा है जिसके ख़ास अहकाम व शरायत हैं जो बहुत ज़रूरी तशरीही और नफ्सीयाती इसरार पर आधारित और हुक्म व मसालह पर आधारित हैं।

(1) रोज़ा सुबह सादिक़ से शुरू होकर सूरज छुपने तक रहता है अगर यह वक्फहा पूरे दिन से कम होता तो इसका कोई विशेष प्रभाव शऊर व तबिअत पर न पड़ता। ज़िन्दगी में ऐसे इत्तेफाक़ होते रहते हैं, कि कई-कई वक्त का खाना नाग़ा हो जाता है, अगर सिर्फ यही हो कि दिन में सिर्फ कुछ घंटों का रोज़ा रखा जाए तो इसका कोई ख़ास अहसास और इस्लाही प्रभाव न पड़ेगा और बहुत से लोगों को ऐसा मालूम होगा कि गोया अपने हिसाब से एक रोज़ ज़रा देर से खाना खाया।

(2) यह रोज़े रमज़ान के तीस या उन्तीस दिन रखे जाते हैं, इस लिए कि ऐसे वक़्फे लगातार हों ताकि इनके नक़ूश देर पा हों। एक लम्बे वक़्फे से यह बहुत अधिक लाभप्रद है कि लगातार विभिन्न प्रकार से अनेक तरह के वक़्फे हों।

(3) इन वक़्फों की संख्या का निर्धारित भी ज़रूरी है कि इसको निर्धारित न करने से संख्या व तफरीत का अंदेशा है। बहुत से लोग बहुत थोड़े रोज़े रखते और बहुत से अधिक रोज़े रखते और फिर जब यह आलिमगीर फरीज़ा है और तशरीअ आम मक्सूद है तो इसमें इन्तेख़ाब का हक़ नहीं रहना चाहिए था कि जो शख़्स जिस महीने में चाहे रोज़े रखे। इससे आम तौरपर हीला जुई, उज़्र और बेअमली का दरवाज़ा खुलता है और गुरेज़ की राह पैदा हो जाती है। अहतसाब और बाज पुर्स का कोई मौक़ा बाक़ी नहीं रहता। वाअज़ व नसीहत, अम्र बिल मारूफ नहीं अनअल मुन्कर का दरवाज़ा बन्द हो जाता है, जिस व्यक्ति से भी किसी वक्त इस बारे में बातचीत की जाए वह य कहकर मुंह बन्द कर सकता है कि मेरा मामूल फलां महीने में है और इसका कोई जवाब नहीं और इस तरह रफ्ता-रफ्ता इस चीज़ का रिवाज़ मिट जाएगा।

(4) एक ही वक़्त में सारी ज़मीन

बाक़ी पेज 11 पर

नूरे क़ुरआन

(सूरा अल बकरह नं॰ 02)

अनुवाद और व्याख्या : शैख़ुल हिन्द र.अ.

वही टोटे वाले हैं।

मतलब यह है कि इन ग़लत कार्यो से अपनी ही हानि करते हैं। इस्लाम और उम्मत के नेक लोगों की तौहीन (मानहानि) कुछ भी नहीं हो सकेगी।

तुम लोग किस प्रकार अल्लाह से इनकारी होते हो हालांकि तुम बेजान थे।

अर्थात्! बेजान शरीर, क्योंकि उसमें चेतना कुछ भी न थी। पहले तत्व थे पश्चात् माता पिता का भोजन बनें फिर वीर्य फिर जमा हुआ खून फिर गोश्त।

फिर तुम उसी की ओर लौटाये जाओगे।

अर्थात् कब्रों से निकल कर अल्लाह के सामने हिसाब किताब के लिए खड़े किए जाओगे, तो अब निर्णय करो कि जब प्रारंभ से अन्त तक अल्लाह के उपकार से दबे हुए हो और हर दशा में उसके आश्रित और उम्मीदवार हो, फिर इस पर भी इंकार करना और उसकी अवज्ञा करना कितनी आश्चर्य की बात है।

रुकू नं॰ 3

वही है जिसने तुम्हारे लिए जो कुछ ज़मीन में है सब पैदा किया, फिर आकाश की ओर आकृष्ट हुआ सो उनको ठीक बना दिये सात आसमान और अल्लाह प्रत्येक वस्तु को जानता है।

इस आयत में दूसरे उपहार का वर्णन किया गया है अर्थात् अल्लाह ने तुमको पैदा किया और तुमको जीवित रखने और लाभ उठाने के लिए, ज़मीन में हर प्रकार की वस्तुएं बनायीं। उसके पश्चात् सात आसमान बनाये गये जिनमें तुम्हारे लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के लाभ है।

और अब आपके पालनहार ने फरिश्तों से कहा मैं ज़मीन में अपना एक नायब (प्रतिनिधि) बनाने वाला हूं।

अब एक बड़े उपहार का वर्णन किया है जो तमाम इंसानों से संबंधित है और वह हज़रत आदम अलै॰ के जन्म का किस्सा जो विस्तार से बयान किया गया है, अल्लाह ने उनको अपना प्रतिनिधि बनाया था। पहली आयत में जो ''जो कुछ ज़मीन में है वह सब तुम्हारे लिए पैदा किया'' कहा था यदि उससे किसी को इंकार हो तो ह॰ आदम अलै॰ के किस्से से भली-भांति उसका उत्तर भी हो गया।

फरिश्तों ने कहा क्या आप ज़मीन में ऐसे लोगों को बनायेंगे जो उसमें कलह और रक्तपात करेगा और हम आपकी अच्छाइयों का हर समय बखान करते रहते हैं और आपकी पवित्र सत्ता को याद करते रहते हैं।

फरिश्तों को जब यह भ्रम हुआ कि ऐसे बन्दे बनाये जायेंगे कि जिनमें ख़राबी पैदा करने वाले और रक्तपात करने वाले होंगे। हम जैसे आज्ञाकारों के होते हुए उनको प्रतिनिधि बनाने का क्या कारण? तो फरिश्तों ने यह बात आपत्ति के रूप में नहीं बल्कि समझने को भी जिनों जैसा समझकर कह दिया। 2. या अल्लाह ने पहले से बता दिया था, 3. या लोहे महफ़ूज़ पर लिखा देखा, 4. या समझ गए कि हाकिम और उत्तराधिकारी की आवश्यकता उसी समय होगी जब अत्याचार होगा। 5. या हज़रत आदम के पुतले को देखकर अनुमान के आधार पर समझ गये होंगे।

अल्लाह ने कहा कि मैं उस बात को जानता हूं जिसको तुम नहीं जानते।

फरिश्तों को तुरंत सारांश रूप में तो यह उत्तर दिया गया कि हम भली-भांति जानते हैं कि उसके पैदा करने में क्या तात्विकतायें हैं जो तुम्हें अभी तक ज्ञात नहीं, अन्यथा उसके उत्तराधिकारी बनने और उसके ऊंचा होने पर कोई शंका न करते।

और अल्लाह ने आदम को सब वस्तुओं के नाम सिखला दिये, फिर उन सब वस्तुओं को फरिश्तों के सामने किया, फिर कहा मुझको इनके नाम बताओ यदि तुम सच्चे हो। फरिश्ते बोले आप पवित्र हैं हमको इतना ही ज्ञात है जितना आपने हमको सिखलाया। निःसंदेह आप ही वास्तविक जानने वाले तत्वज्ञाता है।

सारांश यह है कि अल्लाह हज़रत आदम को प्रत्येक वस्तु का नाम उसकी वास्तविकता और गुण और लाभ हानि के साथ सिखा दिये और विद्या आदम के हृदय में बिना किसी माध्यम के डाल दी क्योंकि इस विद्या के बिना उत्तराधिकारी होना और दुनिया पर राज्य करना संभव नहीं था। इसके पश्चात् फरिश्तों को इस तात्विकता की जानकारी देने के उद्देश्य से फरिश्तों से इन बातों को पूछा गया (जिनका अभी हमने अभी वर्णन किया) कि यदि इस बात में सच्चे हो कि अल्लाह का उत्तराधिकारी बन कर दुनिया का काम संभाल सकते हो तो इन वस्तुओं के नाम और गुण बताओ, परंतु उन्होंने अपनी विवशता को स्वीकार कर लिया और भली-भांति समझ गये कि इस सामान्य ज्ञान के बिना कोई अल्लाह के उत्तराधिकारी होने का कर्तव्य भूतल पर पूरा नहीं कर सकता। यदि हमको इस सामान्य ज्ञान का कुछ आभास प्राप्त भी हो जाये तो इतनी बात से हम उत्तराधिकारी होने के योग्य नहीं हो सकते, यह समझकर कह उठे कि ऐ अल्लाह आपके ज्ञान और परम तत्व तक किसी की पहुंच नहीं।

जनगणना: मात्र आंकड़ा नहीं

एस. मजूमदार

लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में केन्द्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कोविड-19 के चलते जनगणना में देरी की बात कही है। उन्होंने सदन को बताया है कि 28 मार्च 2019 को ही भारत के राजपत्र में इसे अधिसूचित कर दिया गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस काम को अगले आदेश तक टाल दिया गया है हालांकि, देश और समाज के लिहाज़ से जनगणना के महत्व को देखते हुए इसे लंबे समय तक रोके रखना उचित नहीं हे। वैसे भी, जब अन्य सारे दैनिक कामकाज सामान्य रूप से हो रहे हैं, तब इस कार्य को स्थगित रखने का कोई अर्थ नहीं था।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जनगणना के आंकड़े अन्य तमाम आंकड़ों से काफी अलग होते हैं। जहां अन्य आंकड़े सर्वेक्षण पर आधारित होते हैं, जिसमें कुछ लोगों से बातचीत करके निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है, तो वहीं जनगणना की प्रक्रिया घर-घर जाकर पूरी होती है। यह उन निष्कर्षों की सत्यता पर मुहल लगाती है, जो अलग-अलग सर्वेक्षणों से हमें मिलते हैं। जनगणना उन आंकड़ों की कलई भी खोलती है और संशोधन की ज़रूरत (यदि हो तो) भी बताती है

इसके आंकड़े हमें बताते हैं कि देश में जनसंख्या का फैलाव कहां, कितना और कैसा है? बहुत बारीक तौर पर तो नहीं, लेकिन सतही तौर पर ये आंकड़े यह भी बताते हैं कि लोग किन-किन आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हैं। जैसे, 2011 की जनगणना से हमें पहली बार पता चला कि देश में किसानों की संख्या में गिरावट आई है। यहां किसान का अर्थ है कृषि उत्पाद पर नियंत्रण रखने वाली आबादी। वर्ष 2001 में न सिर्फ किसानों की आबादी में कमी देखी गई, बल्कि खेतिहर मज़दूरों की संख्या में वृद्धि का पता चला। इसका अर्थ था कि एक बड़ी आबादी किसान से खेतिहर मज़दूर बन गई। क्या इस प्रवृत्ति पर 2011 से 2021 के बीच रोक लगी या इसमें कमी या बढ़ोत्तरी हुई है? इसकी सही तस्वीर तो नई जनगणना से ही सामने आएगी।

कृषि क्षेत्र की वास्तविक स्थिति को जानना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आमतौर पर हम यही जानते हैं कि हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था बदल रही है और लोग खेती-किसानी छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में काम ढूंढ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि कृषि से उनकी जीने के लिए न्यूनतम आय नहीं हो रही। मगर कुछ सर्वेक्षणों ने यह भी बताया है कि रोज़गार में जुटी आबादी का प्रतिशत घट रहा है। काम से अमूमन महिलाएं बाहर रहा करती थीं, लेकिन अब इसमें पुरुषों की संख्या भी बढ़ रही है, यानि कृषि छोड़ दूसरी गतिविधियों का हिस्सा बनने को आतुर आबादी को भी शायद ही रोज़गार मिल पा रहा है। क्या वाकई ऐसा है? इसकी वास्तविक और प्रामाणिक तस्वीर भी हमें जनगणना से मिलेगी।

जनगणना का एक और महत्व है। शहरों और गांवों में फर्क आमतौर पर प्रशासनिक ढांचों (पंचायत, नगर निगम, महानगरपालिका आदि) से होता है। मगर जनगणना में फर्क का एक और मापक है। इसमें यह देखा जाता है कि कृषि क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों का चरित्र क्या है? अगर किसी इलाके में गैर कृषि कार्यों में जुटी आबादी का प्रतिशत ज़्यादा होता है, तो जनगणना उसे शहरी इलाक़ा मानती है। पिछली जनगणना में शहरी आबादी में बढ़ोत्तरी इसी कारण से हुई थी। उस समय शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या नहीं बढ़ी थी, बल्कि कई क्षेत्रों में चरित्र में बदलाव हो गया था। ज़ाहिर है, जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था का ढांचा बदल रहा है, इस तरह की जानकारियाँ काफी अहम हो जाती हैं।

यह कवायद हमें बताती है कि अलग-अलग क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि का पैटर्न क्या है, काम काज की तलाश में लोगों का पलायन कितना हो रहा है, विस्थापन की वजहें क्या है आदि? समाज और अर्थव्यवस्था के विश्लेषण में इस तरह के आंकड़े काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यह जानना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा असंगठित है। संगठित क्षेत्र के प्रामाणिक आंकड़े तो हमें कई तरीके से मिल जाते हैं। कंपनियों द्वारा आयकर अथवा टीडीएस काटना भी हमें संगठित क्षेत्र की हक़ीक़त कमोबेश बता देता है। मगर असंगठित क्षेत्र को यह लाभ हासिल नहीं है। सैंपल सर्वे में हम महज़ अनुमान लगाते हैं। अगर तय वक़्त पर जनगणना के आंकड़े जारी न हो, तो फिर सैंपल सर्वे के निष्कर्षों पर भी शक बढ़ता जाता है। लिहाज़ा, केवल लोगों की संख्या जानने के लिए नहीं, बल्कि देश की योजनागत तैयारियों के लिए भी जनगणना बहुत ज़रूरी है।

दिक्कत यह है कि जनगणना को ही सिर्फ नहीं टाला गया है, बल्कि जो अन्य सर्वे किए जाते हैं, उनको भी या तो पिछले कुछ सालों में पूरा नहीं किया गया अथवा उनके आंकड़े जारी नहीं किए गए। मसलन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की उस रिपोर्ट को लोकसभा चुनाव तक के लिए टाल दिया गया था, जिसमें बेरोज़गारी दर के पिछड़े साढ़े चार दशक में सर्वाधिक 6.1 प्रतिशत होने की बात कही गई थी, जबकि फरवरी, 2019 में भी यह रिपोर्ट 'लीक' हो गई थी। इसी तरह, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा किए जाने वाले उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के 2017-18 के आंकड़ों को जारी न करने का फैसला किया गया, जबकि मीडिया में ऐसी चर्चा थी कि यह रिपोर्ट उपभोक्ता खर्च गिरने का संकेत दे रही है। यहां यह समझना होगा कि आंकड़ों या उसे तैयार करने की प्रक्रिया का सार्वजनिक होना बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र में फैसले लेने की एक तय प्रक्रिया होती है, जिसमें आंकड़ों की अहम भूमिका है। यदि विशेषज्ञों के पास सही आंकड़े नहीं होंगे, तो वे सार्वजनिक बहसों में अपनी भूमिका नहीं निभा सकेंगे। इन्हीं बहसों के आधार पर तो देश तय करता है कि उसके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं और उसे कौन सी नीतियां अपनानी चाहिए?

बहरहाल, कोविड की वजह से ही यह काम रोका गया है या जातिगत जनगणना संबंधी राजनीतिक मांग की वजह से, इसका जवाब तो अभी सही-सही नहीं दिया जा सकता, लेकिन आंकड़े तैयार करना ज्ञान की प्रक्रिया का गंभीर हिस्सा है। जनगणना चूंकि हरेक हिन्दुस्तानी की गणना है, इसलिए इसका खास स्थान है। वैसे भी, यह एकमात्र ऐसी कवायद है, जिसमें एक-एक भारतीय की हक़ीक़त के कुछ न कुछ पहलू जुटाए जाते है।❑❑

राष्ट्रपति चुनाव में चौंका सकतें हैं मोदी

चार राज्यों में सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद के चुनाव में भी चौंका सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसी संकट को अवसर में बदलने में यकीन करते हैं। अगले कई सप्ताहों के दौरान उन्हें कुछ कड़ी राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना है। यदि वह उन पर क़ाबू पाने में सफल हो जाते हैं, तो यह 2024 के संसदीय चुनावों में उनकी सुचारू वापसी की नींव रख सकता है। वैसे इस वर्ष बजट के रूप में उन्होंने अभी अभी एक बाधा पार कर ली है, जिसे वित्तमंत्री ने 'अमृत काल' का बजट कहा है। मोदी के सामने आगामी चुनौती है, उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव। चूंकि चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार पर लगे तमाम प्रतिबंधों में कुछ ढील दी है, ऐसे में मोदी पांच राज्यों के चुनिंदा जिला मुख्यालयों में जाना चाहेंगे। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे 10 मार्च को आएंगे और तब मोदी की वास्तविक राजनीतिक चुनौती शुरू होगी और वह है अगले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव है। यह देखना होगा कि नरेन्द्र मोदी अपनी पसंद का चुनाव कैसे करेंगे और उनके पास विकल्प क्या है?

पहले बजट पर लौटते हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रभावी ढंग से भाजपा के 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल भाजपा के तकरीबन सभी प्रमुख मुद्दों को अमल में लाया है। दिलचस्प यह है कि मोदी, दिवंगत अरुण जेटली और निर्मला सीतारमण, इन तीनों ने घोषणा पत्र के मसौदे को मंज़ूरी दी थी। बजट में बड़े आर्थिक सुधारों को शामिल किया गया। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल मुद्रा का ज़िक्र भाजपा के घोषणा पत्र में नहीं था, उसे भी भारतीय अर्थ व्यवस्था में जगह दी गई है। मोदी प्रशासन के लिए क्रिप्टो करेंसी एक बड़ी चुनौती हैं। भाजपा ने इस संकट की भी पार कर लिया है। इसकी ज़िम्मेदारी अब रिज़र्व बैंक पर डाल दी गई है।

संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस चल रही है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने काफी उत्तेजक भाषण दिया है, मगर वह भाजपा की चाल में उलझ गए। न तो कांग्रेस और न ही तृणमूल ने कार्यवाही को बाधित किया हैं और इससे मोदी सरकार को पर्याप्त राहत है और अपनी रणनीति पर काम करने का मौक़ा मिला है।

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव को अनेक पर्यवेक्षक मोदी सरकार की दूसरी पारी की मध्यावधि समीक्षा की तरह देख रहे हैं। औसतन हर तीसरे माह में देश के किसी भी कोने में होने वाले चुनाव अपने आप में चुनौती हैं और इन सब में जीतने की इच्छा ने मोदी पर अतिरिक्त दबाव बनाया है। वह अपनी पार्टी के वोट दिलाने वाले सर्वोच्च नेता है और हर चुनाव में अपनी पार्टी का नेतृत्व वही करते हैं। मोदी ने पांच राज्यों में चुनाव प्रचार का एक दौर पूरा कर लिया है। पार्टी के अंदरूनी लोग कहते हैं कि वर्चुअल प्लेटफार्म में भी नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति हज़ारों लोगों की उपस्थिति में होने वाली सभाओं जैसी प्रभावी होती है। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और मणिपुर के चुनाव में विजय हासिल करने में भाजपा को मुश्किलें नहीं आनी चाहिए। लेकिन पंजाब और गोवा में उसे धक्का लग सकता है और इससे मोदी को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 अप्रैल को और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म होगा। मोदी को इन शीर्ष सांविधानिक पदों के उम्मीदवारों के चयन को लेकर काफी मशक्कत करनी होगी। राष्ट्रपति के पिछले चुनाव के समय 2017 में भाजपा के पास भारी बहुमत था, क्योंकि तब शिवसेना और अकाली दल एनडीए का हिस्सा थे। यही नहीं, तब तमिलनाडू में अन्नाद्रमुक दो तिहाई बहुमत के साथ सत्ता में थी और उसने रामनाथ कोविंद का समर्थन किया था। लेकिन अब परिदृश्य बदल गया है। तमिलनाडू में द्रमुक सरकार में है और 2019 में दो केन्द्र शासित क्षेत्रों में बदले जाने के बाद से जम्मू कश्मीर की विधानसभा बहाल नहीं हुई है। इसके अलावा बहुत कुछ पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों पर भी निर्भर करेगा। इसलिए मोदी को राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार की जीत के लिए आवश्यक मत प्राप्त करने के लिए भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है।

इसलिए मोदी को राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार की जीत के लिए आवश्यक मत प्राप्त करने के लिए भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों तथा सारी विधानसभाओं के सदस्यों को मिलाकर इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन किया जाता है। 2017 में दोनों सदनों के 776 सांसदों और 4,120 विधयकों से इलेक्ट्रोरल कॉलेज बनाया गया था। मोदी ने इसके बारे में हाल ही में आरएसएस के नेताओं, भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह के साथ विस्तृत चर्चा

बाक़ी पेज 11 पर

पंजाब किंग्स को पहली आईपीएल ट्रॉफी जीताना ही मेरा लक्ष्य, जितेश शर्मा ने बताया अपना उद्देश्य

पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश शर्मा ने स्कूल स्तर पर केवल चार प्रतिशत अतिरिक्त अंक प्राप्त करने के लिए क्रिकेट को अपनाया था। जब वह हाई स्कूल में पीसीएम भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित में अच्छे अंक प्राप्त करने का लक्ष्य बना रहे थे, तो उन्हें क्रिकेट में आने का अवसर मिला था और जिसके बाद उन्होंने क्रिकेट में अपनी एक नई शुरुआत की। हालांकि क्रिकेट उनका पहला मनपसंद खेल नहीं था, लेकिन बाद में उनके खेल करियर में इसका भरपूर लाभ मिला।

जितेश 3 अप्रैल को ब्रेबोर्न में चेन्नई सुपर लकग्स (सीएसके) के खिलाफ पंजाब फ्रेंचाइजी की 54 रन की जीत में प्रमुख खिलाड़ियों में से एक के रूप में उभरे।

28 वर्षीय क्रिकेटर ने पहली बार अपनी टीम के 180/8 में 17 गेंदों में 26 रन बनाए और फिर दो कैच लिए - जिसमें 23 पर महेंद्र सिंह धोनी भी शामिल थे, जिससे पीबीकेएस ने सीएसके को 18 ओवर में 126 रन पर ही समेट दिया था।

शर्मा ने पीबीकेएस वेबसाइट पर कहा कि उस समय मैंने चार प्रतिशत अतिरिक्त अंक लेने के लिए क्रिकेट में राज्य-स्तरीय प्रतियोगिताओं में टीम का प्रतिनिधित्व किया था।

शर्मा ने कहा कि इसके अलावा, मैं फुटबॉल (पहला प्यार) खेलना भी मिस करता था। मैं इसे ध्यान में रखते हुए क्रिकेट खेलना चाहता था।

उन्होंने अपना पहला बल्ला 17 साल की उम्र में उठाया, टीम में शामिल होने के लिए आवश्यक शर्तें पूरी करने के बाद राज्य के लिए खेलते हुए शर्मा ने विकेटकीपिंग भी की, जिसके लिए कोई कोचिंग भी ... कोशल पर भरोसा करते थे। उन्होंने कहा कि एक सही स्ट्राइकर के रूप में खेलने से उन्हें स्टंप के विकेटकीपिंग करने में मदद मिली।

भारतीय वायु सेना में शामिल होने की महत्वाकांक्षा के साथ अध्ययन करने वाले शर्मा ने कहा कि उन्हें ... क्रिकेट में आ जाएंगे।

शर्मा ने कहा कि जब मैं एक बच्चा था, तो मैं भारतीय वायु सेना में जाने की सोचता था। मेरी पृष्ठभूमि सेना से काफी जुड़ी हुई है। मेरे परदादा सुभाष चंद्र बोस के लिए एक ड्राइवर थे, जब भारतीय राष्ट्रीय सेना सीमा पर थी। उन कहानियों को सुनने के बाद, मैं भारतीय सेना में जाना चाहता था। प्लास्टिक की गेंदों से खेले जाने वाले गली क्रिकेट ने सबसे पहले एक प्रसिद्ध कोच का ध्यान शर्मा ने खींचा।

शर्मा ने कहा कि मैं फुटबॉल की ओर अधिक आकर्षित हुआ क्योंकि यह शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण खेल था। यह मेरे लिए स्वाभाविक रूप से आया था। इसलिए मैं स्कूल और दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता था, लेकिन उनकी स्कूल टीम फुटबॉल के मामले में उतनी अच्छी नहीं थी और प्रबंधन ने क्रिकेट खेलने वाले व्यक्ति के लिए अतिक्ति भत्ते की पेशकश की। शर्मा ने कहा कि इस सीजन में उनका उद्देश्य पंजाब किंग्स को अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीतने में मदद करना है।□□

ओलंपिक 2028 : कई खेलों पर मंडरा है ओलंपिक से बाहर होने का संकट

भविष्य में शायद ऐसा मुमकिन हो की अनेक खेल जो आज खेले जा रहे हैं ओलंपिक्स प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए लिटिंग ही न हो। मुक्केबाज़ी, भारोत्तोलन और मॉडर्न पेंटार्थलान को लास एंजिल्स में 2028 में होने वाले ओलम्पिक खेलों में अपना स्थान बरकरार रखने के लिए 18 माह के अंदर अपनी व्यवस्था में सुधार करने के लिए कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सतिमि (आईओसी) के अध्यक्ष थॉमस बाक ने मुक्केबाज़ी और भारोत्तोलन के शासी निकायों के बारे में कहा कि वे हमेशा समस्याएं पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि इन खेलों में नेतृत्व से जुड़े मसलों और भ्रष्टाचार और डोपिंग के मुद्दों पर चिंता व्यक्त की। मॉडर्न पेंटाथलान को आइओसी ने अपनी स्पर्धाओं से घुड़सवारी को हटाने के लिए कहा है जिस पर खिलाड़ियों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

इन तीनों खेल को ओलंपिक 2028 के कार्यक्रम की शुरूआती सूचि में शामिल नहीं किया गया है। इस कार्यक्रम को मंजूरी के लिए फरवरी में आईओसी सदस्यों के सामने रखा जाएगा। सूचि में स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग शामिल हैं। ये तीनों खेल पहली बार तोक्यो ओलंपिक में शामिल किए गए थे। इससे वे भविष्य में ओलंपिक प्रसारण कार्यक्रम से होने वाली आय हासिल करने के हक़दार भी बन जाएंगे जो प्रति खेल कम से कम एक करोड़ 50 लाख डॉलर है। जिन तीन खेलों को हटाया गया है उनके पास अब भी सूचि में शामिल होने का मौका रहेगा। बाक ने कहा कि उन्हें आईसीसी कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों को अपने खेल के शासन और संगठनात्मक संस्कृति में बदलावों से संतुष्ट करना होगा।

पेट दर्द के अनेक कारण हो सकते है

पेट दर्द सबको समय-समय पर हो जाता है। लक्षणों के आधार पर डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता हो सकती है। आईये जाने क्या-क्या समस्या हो सकती है जिनसे पेट दर्द होता है।

गैस्ट्रिटिस

भोजन को पचाने में मदद करने वाले तरल में बहुत अधिक एसिड होता है। अगर पेट सुरक्षात्मक बाधा म्यूकस न हो तो एसिड पेट को नुकसान पहुंचा सकता है परत को काट सकता है। जब इस म्यूकस की लेयर कम हो जाती है या एसिड स्त्राव (सेक्रीसन) ज़्यादा होता है तो अमाशय की परत में जलन होने लगती है जिसे गैस्ट्रिटिस कहा जाता है। बैक्टीरिया, आईब्रुप्रोफेन, बहुत अधिक शराब, या तनाव जैसे दर्द रिलीवर के नियमित उपयोग द्वारा भी हो सकता है। आप कभी-कभी इसे ओवर द काउंटर एंटासिड या प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के साथ इलाज कर सकते हैं।

पेस्टिक अल्सर

उपरोक्त कारणों से पेट की परत या छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में घाव हो सकते हैं। इसका आम कारण बैक्टीरिया है लेकिन एस्पिरीन, आईबुप्रोफेन और अन्य दर्द निवारक दवाओं के दीर्घकालिक उपयोग से भी हो सकता है। धूम्रपान करते हैं या तम्बाकू खाते हैं, उन्हें ये अल्सर अधिक बार मिलता है।

वायरस या गैस्ट्रिक फ्लू

पेट फ्लू आंतों में एक वायरल संक्रमण है। इससे पतले पानीदार दस्त, ऐंठन या मतली हो सकती है, यह किसी संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने या उसके साथ तौलिये आदि सांझा करने या दूषित संक्रमित भोजन के माध्यम से हो सकता है। इसका कोई इलाज नहीं है, केवल लक्षणों का इलाज यथा बुख़ार की दवा निर्जलिकरण डी हाइड्रेशन हेतु जीवन रक्षक घोल ले सकते हैं। या बचाव हेतु हाथ धोना व वस्त्र साझा न करना संक्रमित भोजन से बचना जैसे उपाय कर सकते हैं।

खाद्य विषाक्ता
फूड पाइजनिंग

भोजन में बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी इस बीमारी का कारण बनते हैं। फूड पाइजनिंग से दस्त, मतली और उल्टी हो सकती है। यह संक्रमित भोजन खाने से होता है। यह आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन यदि आप निर्जलित यानि डी हाइड्रेशन से ग्रसित हैं और जीवन रक्षक घोल से ठीक नहीं हो रहे तो तुरंत चिकित्सीय मदद लें चिकित्सक आइ वी फ्लूइड व एंटी बायोटिक दे सकते हैं। अगर किसी को फूड पॉइजनिंग के कोई लक्षण हैं और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हैं या फिर कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली कोम्प्रोमिज्ड इम्युनिअी यथा एच आइ वी या अन्य रोग है तो उसे तुरंत चिकित्सीय सहायता लेनी चाहिए।

अपेंडीसाइटिस - परिशिष्ट

(अपेंडीक्स) एक उंगली के आकार का अंग है जो पेट के निचले दाहिने हिस्से में की शुरूआत में पाया जाता है। यह जानवरों तथा ऊंटों में तो भोजन संग्रह का काम करता है लेकिन मानव में धीरे धीरे सिकुड़ गया है क्योंकि सदियों से मानव शरीर को भोजन भंडारण की ज़रूरत नहीं रही। यह स्पष्ट नहीं है कि यह मानव शरीर में अब क्या करता है, लेकिन जब यह संक्रमित होकर सूजन कर देता है तो फट भी सकता है तब इसे निकालने हेतु ऑपरेशन करना पड़ता है क्योंकि इसके फटने से बैक्टीरिया सारे पेट में फैल सकते हैं। पहले पेरिटोनाइटिस फिर मृत्यु तक हो सकती है। शुरुआत में एंटी बायोटिक व आइ वी फ्लूइड से ठीक हो सकता है लेकिन बार बार होने की शंका होती है।

गाल स्टोनज

आमतौर पर पित्ताशय की पथरी - उन टयूबों या नलिकाओं को ब्लॉक कर देती हैं जिनके द्वारा बाइल नामक द्रव्य जिगर व अग्न्याशय द्रव्य, पित्ताशय की थैली से छोटी आंत तक पहुंचता है के बीच चलते हैं। आम लक्षण पेट दर्द है- मतली, उल्टी बुखार, गहरे रंग का मूत्र और हल्के मटमैले रंग का मल भी हो सकते हैं। पत्थर अक्सर अपने आप निकल सकते हैं लेकिन अगर वे नहीं निकलते तो सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है।

हर्निया

हर्निया तब होता है जब आंतों का एक हिस्सा के पेट की दीवार के माध्यम से स्लाइड करता है। जब यह मुड़ जाता है यानि मरोड़ खा लेता है तो मरोड़ के बाद के हिस्से की रक्त की आपूर्ति से कट जाती है, जिस तरह हर्ट अटैक में हर्ट, यह आपके पेट में गंभीर दर्द पैदा कर सकता है। समस्या को ठीक करने के लिए अक्सर सर्जरी की जल्दी ज़रूरत होती है।

क़ब्ज़: सप्ताह में तीन से कम मल त्याग होने पर कब्ज़ होना माना जाता है। व्यायाम, ख़ूब पानी और ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें बहुत सारे फाइबर खाना जो कब्ज़ नहीं होने देते इसमें बचाव कर सकते हैं होते हैं, साबुत अनाज सलाद आदि, मदद कर सकते हैं, कब्ज़ भी पेट दर्द कारणों में से एक हो सकता है।

अग्न्याशय शोथ

ऐसा तब होता है जब अग्न्याशय (पेंक्रीआज) जो शरीर को चीनी की प्रक्रिया में मदद करता है और भोजन को पचाता है, सूजन हो जाता है ऊपरी पेट में दर्द हो सकता है जो खाना खाने के बाद बढ़ जाता हैं बुख़ार मतली व उलटी हो सकती है, गंभीर स्थिति में आइफ्लूइड व एंटी बायोटिक से उपचार कियाजाता है।□□

जल्द ही फिर लाया जाएगा कृषि कानून - बीजेपी सांसद का दावा

बीजेपी सांसद सुरेश गोपी ने दावा किया है कि वापस लिए गए कृषि कानून जल्द ही वापस लाए जाएंगे। सुरेश गोपी ने कहा कि देश के असली किसान इन कानूनों को चाहते हैं और अगर इन्हें वापस नहीं लाया गया तो ये किसान सरकार बदल देंगे। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी राज्यसभा सांसद हैं वे केरल में विशु कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का आदमी हूं, मैं कृषि कानून वापस लिए जाने से बेहद नाराज हूं। आपको अच्छा लगे या बुरा, लेकिन मेरा मानना है कि यह कानून वापस आएंगे। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि देश के असली किसान इन कानूनों को चाहते हैं, मुझे भरोसा है कि इन कानूनों की वापसी होगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे सरकार बदल देंगे। गौरतलब है कि इन कृषि कानूनों के खिलाफ देशभर के किसान सड़कों पर उतर आए थे और उनका आंदोलन साल भर से भी अधिक समय तक चला था। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी जिसके बाद संसद में इसे वापस ले लिया गया था। किसानों ने इन्हें काले कानून की संज्ञा दी थी और उनका तर्क था कि इन कानूनों के लागू होने से देश का कृषि क्षेत्र कार्पोरेट के हाथों में आ जाएगा और किसान अपने ही खेत में मजदूर बनकर रह जाएगा। इसके अलावा किसानों ने एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की थी जिसे लेकर सरकार ने वादा किया था कि इसके लिए कमेटी बनाकर जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन इस विषय में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इससे पहले एक विवाद भी खड़ा हो गया था जब गोपी ने विशु कार्यक्रम में कुछ पुजारियों को पैसे देकर उन्हें बांटने को कहा था। ध्यान रहे कि मंदिर बोर्ड ने किसी भी निजी व्यक्ति से चंदा लेने पर पाबंदी लगा रखी है। लेकिन गोपी ने थिरुसूर में कई मंदिरों को पुजारियों को पैसे देकर कहा था कि इन्हें एक हजार बच्चों में बांटा जाए।

शेष.... प्रथम पृष्ठ

प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे इस फिल्म में कहीं ज़िक्र नहीं है इसलिए कि वी.पी. सिंह की सरकार को खुद उनकी आक़ा भाजपा बाहर से सपोर्ट कर रही थी अगर वी.पी. सिंह का ज़िक्र होता तो बात का भाजपा तक पहुंचना लाज़िमी थी यह फिल्मकार का दोगलापन है जो स्वयं ही प्रदर्शित होता है।

इससे कौन इंकार कर सकता है कि 1988-89 को कश्मीर में खूनी साल कहा जा सकता है उन दो सालों में वहां आतंक पूरे चरम पर था। मगर प्रश्न यह है कि आख़िर उसका ज़िम्मेदार कौन है, क्या उस समय के शासकों को क्लीन चिट दी जा सकती है जबकि यह बात साबित हो चुकी है कि उस समय फारुक अब्दुल्ला सरकार को वी.पी. सिंह सरकार ने भाजपा की ज़िद पर बर्खास्त किया था, जगमोहन भी जिन्हें राज्यपाल बनाकर भेजा गया था भाजपा का चहेता अधिकारी था और जिसने कश्मीरी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए पहले आतंकवादियों को कश्मीरी पंडितों पर हमलों का अवसर दिया और फिर उनकी सुरक्षा के नाम पर उनके डर का फायदा उठाकर उन्हें हिजरत पर मजबूर किया और फिर बसों में भरकर उन्हें ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया, इस हिजरत पर आज तीस वर्ष का समय बीत चुका है, मगर कश्मीरी आज भी वहीं खड़े हैं जहां तीस वर्ष पहले खड़े थे, उनकी हिजरत के बाद भाजपा पिछले दो साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में और पिछले 8 वर्ष से लगातार मोदी जी के नेतृत्व में देश पर सत्ता के मज़े लूट रही है क्या वह बताएंगे कि इन चौदह सालों में भाजपा सरकारों ने उन कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए क्या क़दम उठाए और केवल यही नहीं अभी कुछ वर्ष पहले तो लगातार तीन सालों तक खुद जम्मू कश्मीर में भी भाजपा मुफ़्ती सरकार में अहम भागीदार के रूप में शामिल रही है, इन तीन सालों में उसने उन मज़लूम कश्मीरी पंडित के लिए क्या किया।□□

शेष.... क्रिकेट का सफल नायक...

पहले एक सिद्धांत पेश किया था, जिसमें उन्होंने अतीत को भूलकर पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने और आर्थिक मुद्दों पर ध्यान देने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट का जो नया फैसला आया है उससे सब अंक सही बैठे तो बाजवा को एक और सेवा विस्तार मिलना तय है और वह अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाएंगे, जो भारत के लिए स्वागत योग्य क़दम होगा।

संसद में प्रधानमंत्री और विपक्ष के बीच गतिरोध के दौरान सेना 'तटस्थ' थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इमरान ख़ान ने कहा कि केवल जानवर ही तटस्थ रहते हैं। इस बयान ने उनकी नियति तय कर दी और उसके बाद तो जो हुआ, वह अपने आप में इतिहास है, जो धीरे-धीरे सामने आया है। विश्लेषकों का मानना है कि इमरान की यह हार चीन के लिए झटका होगा। दूसरी ओर, इमरान के चलते अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिश्ते पूरी तरह ख़राब हो गए हैं। अस्थिर पाकिस्तान भारत के हित में नहीं है और यदि वहां नई सरकार आती है, तो बाजवा का सिद्धांत लागू हो सकता है, और द्विपक्षीय रिश्तों में थोड़ी सी उम्मीद जग सकती है।□□

शेष.... फरीज़ा-ए-रमज़ान की हिकमतें

के मुसलमानों के रोज़ा रखने में बड़ी हिकमत है। मुसलमानों की बड़ी जमाअत का फरीज़ा रमज़ान को अहतमाम के साथ एक वक्त में अदा करना, कमज़ोर तबिअत वालों के लिए भी हिम्मत अफ़्ज़ा, शौक अंगेज़ और फर्ज़ की अदायगी में मददगार साबित होता है। एक आलमगीर रूहानी माहौल और एक उमूमी दीनी फिज़ा पैदा हो जाती है। जो कुलूब व अरवाह के लिए मौसम बहार की सी तासीर रखती है जिसमें थोड़ी तवज्जो से हर चीज़ में नशो-नुमा पैदा होने लगता है। मुसलमानों के इस रूहानी फरीज़ा में मशगूल होने से मलकूती अनवर व बरकात का नुज़ूल होता है और जनता के आइना दिल पर अनवार का इन्अकास होता है, मुसलमान आलम के जिस कोने में भी हों उस को रोज़ेदाराना फिज़ा मालूम होती है जो उससे खुद ही तक़ाज़ा करती है कि वह भी रोज़ेदार हो मुसलमान रोज़ा शिकनी करके अपने को इस माहौल में अजनबी और एक तरह का मुजरिम समझता है।

(5) इन सारी हिकमतों के आधार पर साल में एक पूरा महीना रोज़े के लिए मख़्सूस कर दिया गया। दूसरी विशेषता के अलावा जिनका हमें इल्म नहीं रमज़ान की तख़्सीस की एक खुली वजह यह है कि इस माह मुबारक में नुज़ूल क़ुरआन का सिलसिला शुरू हुआ और रोज़ा और क़ुरआन में ख़ास मुनासबत है। क़ुरआन चूंकि आलमे ग़ैब और आलम-ए-रूहानियत की चीज़ है और रोज़ा आलममादी से बहुत हद तक आज़ादी, कल्ब व रूह में लताफत और आलम ग़ैब और आलम रूह से एक तरह की मुनासबत पैदा कर देता है रोज़ेदार पर ख़ुदा की सिफात का एक परतू और उसकी शाने समदीयत का एक असर पैदा हो जाता है इसलिए क़ुरआन के दिल में बसने और रूह में पेबस्त होने का ख़ास मौक़ा होता है, यही वजह है कि क़ुरआन के हिस्से को विभिन्न तरीक़ों से रोज़े में ज़्यादा से ज़्यादा दाख़िल किया गया और यही तरावीह की हिकमत है।

(6) रोज़ा ज़िंदगी में एक ऐसा महसूस फर्क़ और इम्तियाज़ पैदा कर देता है कि बेहिस से बेहिस इंसान को भी अपने पूर्व की जीवन शैली, ग़फ़लत शायरी और दुनियावी इन्हमाक में तख़्फ़ीफ़ का तबयी तक़ाज़ा पैदा हो जाता है।

शेष.... मंज़र पस-मंज़र

राष्ट्र के लिए यह संभव नहीं है कि वह इतनी बड़ी जनसंख्या को रोज़गार दिलवा सके। रोज़गार की तलाश में दिन-रात एक कर रहे व्यक्तियों की संख्या, साधनों और उपलब्ध अवसरों की संख्या से कहीं अधिक है। यही कारण है कि आज भी अधिकांश युवा बेरोज़गारी में ही जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हैं।

हालांकि नब्बे के शुरुआती दशक में निजीकरण और उदारीकरण जैसी नई आर्थिक नीतियों के भारत में पदार्पण करने के साथ ही भारत की रोज़गार स्थिति को थोड़ा बहुत समर्थन मिला। इन्हीं नीतियों के कारण कई ऐसे उद्योगों का विकास हुआ जिनके कारण बेरोज़गारी से संबंधित आंकड़े में कमी देखी गई है। आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी, जिन्होंने हमारे युवाओं के जीवन स्तर को सुधारने में काफी सहायता की, भारत में अपने पांव पसारने में सफल रहीं। लेकिन यह विकास केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है। असली भारत जो ग्रामों में वास करता है, के विकास को उपेक्षित ही रहने दिया गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब देश का शासन भारतीय नेताओं के हाथ में आया तो उन्होंने औद्योगिकीकरण और शहरों के विकास को ही अपनी प्राथमिकता समझते हुए विकास संबंधी सभी योजनाएं केवल शहरी जीवन पर ही केन्द्रित रखीं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कोई महत्वपूर्ण स्थान सुनिश्चित नहीं किया गया। बेरोज़गारी से जुड़ा मसला केवल बढ़ती जनसंख्या तक ही सीमित नहीं है। हमारी व्यवस्था और उसमें व्याप्त कमियां भी इसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। भ्रष्टाचार ऐसी ही एक सामाजिक और नैतिक बुराई है। कोरोना महामारी के दौरान भी बेरोज़गारी काफी बढ़ी है।

बीती 10 मार्च को पांच राज्यों में सम्पन्न हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद। अपने अपने राज्यों में सरकारों ने काम शुरू कर दिया है। पंजाब में मुख्यमंत्री और कैबिनेट ने शपथ कर ली है। यहीं नहीं, कैबिनेट ने एक माह के भीतर 25,000 पदों पर भर्तियां करने का फैसला भी ले लिया। शीघ्र ही इन नौकरियों को सार्वजनिक रूप से विज्ञापित कर दिया जाएगा। करीब 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज़ पंजाब पर है। इन नौकरियों के लिए बजट भी तय करना है। फिर भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपना चुनावी वायदा पूरा करने की कोशिश की हैं जानकारों के मुताबिक देश में 36 राज्यों और सं शासित प्रदेश हैं। यदि एक अन्य औसतन 20,000 नौकरियां निकालें, तो 07 लाख से ज़्यादा रिक्तियां तुरंत भरी जा सकती हैं। अब राज्य सरकारों को इस दिशा में ठोस क़दम उठाने होंगे।

एक स्वागतयोग्य क़दम

दिल्ली के गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल में एंजियोप्लास्टी को सस्ता कर दिया जाना स्वागतयोग्य क़दम है। दिल की धमनियों में ब्लाकेज दूर करने के लिए की जाने वाली एंजियोप्लास्टी में अब मरीज़ों को स्टेंट के लिए अधिक पैसे देने की नहीं पड़ेंगे। पिछले दिनों मरीज़ों को सस्ता स्टेट मिलना शुरू हो गया है। पिछले इसी अस्पताल में एक स्टेंट के लिए 23,625 रुपये का खर्च आता था, जबकि अब यहां पर 9450 रुपये में ही मिल रहा है। दिल की बीमारियों के लिए राजधानी में प्रमुख अस्पतालों में से एक जीबी पंत के प्रबंधन ने स्टेंट के लिए पांच कंपनियों के टेंडर मंज़ूर किए हैं। अस्पताल प्रबंधन मरीज़ों को पांच कंपनियों के स्टेंट उपलब्ध करा रहा है, जिनकी कीमत 9450 रूपये से शुरू होकर 23,620 रुपये तक है। यही नहीं, इतनी कम कीमत पर मिलने के बावजूद ये स्टेंट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से स्वीकृत होने के साथ ही दवा युक्त भी है।

जी.बी. पंत अस्पताल प्रबंधन का यह क़दम दिल के मरीज़ों के लिए काफी लाभदायक है।यदि एंजियोप्लास्टी के दौरान किसी मरीज़ा को एक से अधिक स्टेंट लगाने पड़ते थे तो मरीज़ो की जेब पर इसका काफी बोझ पड़ जाता था। फिलहाल जी.बी. पंत अस्पताल में सस्ते स्टेंट की सुविधा शुरू की गई है, वहीं इसे जल्द ही दिल्ली सरकार के राजीव गांधी सुपर स्पेशियालिस्ट अस्पताल व जनकपुरी स्थित सुपर स्पेशयलिटी अस्पताल में भी शुरू कर दिया जाएगा, जिससे मरीज़ों को इसका अधिकाधिक लाभ मिल सकेगा।

केन्द्र सरकार ने अस्पतालों में आपातकाल में पहुंचने वाले मरीज़ों के लिए ये मुफ्त है, लेकिन अन्य मरीज़ों के लिए स्टेंट का मूल्य करीब 23 हजार रूपये है। जीबी पंत अस्पताल की तरह ही केन्द्र सरकार के अस्पतालों में भी मरीज़ों को सस्ता स्टेंट उपलब्ध कराने के प्रयास होने चाहिए, ताकि वहां पहुंचने वाले मरीज़ों को भी इसके लिए अधिक ख़र्च न करना पड़े।□□

शेष.... राष्ट्रपति चुनाव में...

की। ऐसे कयास हैं कि आरएसएस ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए अपनी पसंद के उम्मीदवारों के कुछ नाम भी सुझाए हैं। कहा जाता है कि मोदी इस बार में देश के शीर्ष सांविधनिक पद पर किसी दक्षिण राज्य, संभवतः तमिलनाडू से किसी महिला को देखना चाहते हैं। संभावित उम्मीदवारों में दो राज्यपालों के नाम है।

एक बात बहुत स्पष्ट दिख रही है कि न तो कोविंद को दूसरा कार्यकाल मिलने जा रहा है और न तमिलनाडू को पदोन्नत करने पर विचार हो रहा है। संभवतः इस बारे में जुलाई के पहले सप्ताह में ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा और मोदी की शैली के अनुरूप कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है।□□

SHANTI MISSION (HINDI WEEKLY) NEW DELHI Postal Registration No. DL(C)-01/1266/2021-23
Publishing Date : 10 April 2022 Posting Days : MON-TUE. at N.D.P.S.O. New Delhi-110002 R.N.I. 57270/93

मंज़र पस-मंज़र — मीम.सीन.जीम

बेरोज़गारी से निपटना बड़ी चुनौती

एक स्वागतयोग्य क़दम

बेरोज़गारी से निपटना बड़ी चुनौती

बेरोज़गारी देश की पुरानी लाइलाज बीमारी है। पिछले 07 सालों में तमाम सरकारें देशभर में आयी और गयी। अमूमन हर राजनीतिक दल ने बेरोज़गारी ख़त्म करने के वादे भी किये, लेकिन हालत में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। हमारे देश में बेरोज़गारी की जड़ें काफी गहरी हैं, और ये समस्या हर बदलते दिन के साथ अहम होती जा रही है। इस समस्या का दुखद पहलू यह है कि जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा काम करने की योग्यता के बावजूद काम करने की योग्यता के बावजूद काम के बग़ैर है तो वहीं केन्द्र और राज्य सरकारों के पास इस समस्या का कोई ठोस हल नहीं है। सरकारें बेरोज़गारी को भी ख़ारिज करती रहती हैं, जबकि यह अर्थ व्यवस्था के लिहाज़ से भी एक गंभीर चुनौती है।

बेरोज़गारी का आंकड़ा भयावह रूप धारण कर चुका है, इसका सामना करना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बीती जनवरी को उत्तर भारत के कई हिस्सों में उन छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, जो रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की ग़ैर तकनीकी श्रेणियों की परीक्षा में शामिल हुए थे। इस परीक्षा में से 35,000 रिक्त पदों को भरा था, जिसके लिए 1.25 करोड़ अभ्यार्थियों ने आवेदन दिया था।

आज़ादी के बाद से बेरोज़गारी का आंकड़ा बढ़ते-बढ़ते इतना विकराल और भयावह रूप धारण कर चुका है कि इसका सामना करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बीती जनवरी को उत्तर भारत के कई हिस्सों में उन छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, जो रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की ग़ैर तकनीकी श्रेणियों की परीक्षा में शामिल हुए थे। इस परीक्षा में से 35,000 रिक्त पदों को भरा था, जिसके लिए 1.25 करोड़ अभ्यार्थियों ने आवेदन दिया था। 1.25 करोड़ कोई छोटी संख्या नहीं हैं यह देश मे 20 से 25 वर्ष की कुल आबादी का करीब 10 प्रतिशत हिस्सा है। इसी संख्य से देश में बेरोज़गारी की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है।

देश में दिसंबर 2021 तक 5.3 करोड़ लोग बेरोज़गार हैं। इन आंकड़ों की जानकारी ईकोनामिक्स टाइम्स ने डेटा सेंटर फॅार मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आधार पर दी है। इनमें से 3.5 करोड़ लोग तो वो हैं, जो एक्टिवली रोज़गार की तलाश में हैं। मतलब ये लोग तो मेहनत करके रोज़गार की तलाश में हैं और उन्हें जल्द से जल्द रोज़गार की आवश्यकता है। इसमें से 8 मिलियन संख्या महिलाओं की है। वहीं, 17 मिलियन यानि 1.7 करोड़ लोग वो हैं, जिन्हें काम चाहिए मगर वो सक्रिय होकर अभी जॉब नहीं ढूंढ रहे हैं। इसमें महिलाओं की संख्या 9 मिलियन है। सीएमआईई का कहना है कि विश्व बैंक ने वर्ष 2020 में महामारी की मार में वैश्विक रोज़गार दर 55 प्रतिशत और 2019 में 58 फीसदी आंकी थी, जबकि भारत 43 प्रतिशत के स्तरपर था। हालांकि सीएमआईई के अनुसार यह दर 38 प्रतिशत है। वहीं, अगर भारत ग्लोबल एम्पायमेंट रेट स्टेंडर्ड तक पहुंचना चाहे तो भारत को 187.5 मिलियन लोगों को रोज़गार देना होगा। बीते दिनों नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने आंकड़े जारी किए हैं कि भारत में रोज़गार की कितनी पतली और दयनीय स्थिति है। एनएसएसओ के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षणों ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उनमें हम अप्रैल, जून 2021 की तिमाही का ज़िक्र करेंगे ये आंकड़े युवा शक्ति वाले भारत का ढिंढोरा पीटने वालों को सवालिया साबित करते हैं। रोज़गार सबसे बुनियादी और अहम समस्या हैं रोटी, कपड़ा, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि रोज़गार से ही जुड़े हैं। सर्वे में 15-29 आयु वर्ग के युवाओं को शामिल किया गया है। अप्रैल-जून 2021 की तिमाही के दौरान इस आयु वर्ग में बेरोज़गारी दर करीब 25.5 फीसदी थी। जब कोरोना वायरस की पहली मार हम पर पड़ी थी, तब तो यह दर करीब 35 प्रतिशत थी। सर्वेक्षण के मुताबिक, देश में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी करीब 47 प्रतिशत केरल में रही है। उसके बाद करीब 46 प्रतिशत बेरोज़गारी दर के साथ जम्मू कश्मीर का स्थान था।

छत्तीसगढ़ में बेरोज़गारी 40 प्रतिशत से ज़्यादा थी। उत्तराखंड में करीब 36.6, राजस्थान में 35,2 तमिलनाडु में 28.5, तेलंगाना में 27.4 और उ.प्र. में 24.7 प्रतिशत थी। महिलाओं में बेरोज़गारी दर और भी भयावह रही है। जम्मू कश्मीर में 67.3 प्रतिशत और केरल में 59.2 प्रतिशत बेरोज़गारी दर महिलाओं में पाई गई है। संभव है कि अब तक इस दर में गिरावट आई होगी, लेकिन आज भी केन्द्र सरकार के तहत करीब 8.72 लाख नौकरियां ख़ाली पड़ी है। यदि केन्द्र और राज्य सरकारों के आंकड़ें मिला लिए जाएं, तो 60 लाख से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। सरकारें इन रिक्तियों पर भर्ती क्यों नहीं करतीं? ये पद तो स्वीकृत होंगे और उनका बजट भी तय हो चुका होगा, फिर भी साल-दर-साल बेरोज़गारी क्यों बढ़ती जा रही है?

फिलहाल जी.बी. पंत अस्पताल में सस्ते स्टेंट की सुविधा शुरू की गई है, वहीं इसे जल्द ही दिल्ली सरकार के राजीव गांधी सुपर स्पेशयालिस्ट अस्पताल व जनकपुरी स्थित सुपर स्पेशयलिटी अस्पताल में भी शुरू कर दिया जाएगा, जिससे मरीज़ों को इसका अधिकाधिक लाभ मिल सकेगा। केन्द्र सरकार ने अस्पतालों में आपातकाल में पहुंचने वाले मरीज़ों के लिए ये मुफ्त है।

भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। जनसंख्या जितनी तेज़ी से विकास कर रही है, व्यक्तियों का आर्थिक स्तर और रोज़गार के अवसर उतनी ही तेज़ गति से गिरते जा रहे हैं। भारत जैसे विकासशील

बाक़ी पेज 11 पर

राम नवमी के अवसर पर हिंसात्मक घटनाओं पर जमीयत उलेमा ने लिखा गृहमंत्री को पत्र

राम नवमी के त्योहार के अवसर पर देश के कई राज्यों विशेषकर मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई साम्प्रदायिक हिंसा और इसके बाद सरकार एवं प्रशासन द्वारा आरोपियों के घरों और दुकानों के विध्वंस पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने कड़ी आपत्ति और चिंता व्यक्त की है। मौलाना मदनी ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि दंगाइयों ने देश में आदत बना ली है कि वह मुस्लिम मोहल्लों में नफरत पर आधारित नारे लगाते हैं, वहां अत्यधिक भड़काऊ कृत्यों को अंजाम देते हैं और मस्जिदों और मस्जिदों एवं इबादतगाहों का अपमान करते हैं। उन्हें इस सम्बंध में कानून व्यवस्था की तरफ से कोई बाधा या कठिनाई भी नहीं है। मौलाना मदनी ने इस सम्बंध में गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर ध्यान आकर्षित कराया है कि वह ऐसी बेकाबू हो रही स्थिति पर रोक लगाएं और देश को अराजकता की राह पर लगातार चलने से रोकें। मौलाना मदनी ने विशेषकर मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई घटना पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि यहां अल्पसंख्यक समुदाय को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। असामाजिक तत्वों के जरिए कई घरों और धार्मिक स्थलों को आग के हवाले कर दिया गया। यह देखना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंसा फैलने के बाद अब स्थानीय प्रशासन अल्पसंख्यक समुदाय को परेशान करने पर तुला हुआ है। मुस्लिम संपत्ति और उनके घरों को चिंहित कर के तोड़ा जा रहा है। यही नहीं यह भारत में अदालतों द्वारा अपनाया गया एक सामान्य कानूनी सिद्धांत है कि जब तक कोई आरोपी दोषी साबित न हो जाए, उसके साथ निर्दोषों की तरह ही व्यवहार किया जाएगा। लेकिन अब मध्य प्रदेश की सरकार घरों को गिराकर भारत के संविधान का उल्लंघन करते हुए फासीवादी कृत्य को अंजाम दे रही है।

मौलाना मदनी ने गृह मंत्री से शिकायत की कि जमीयत उलेमा की स्थानीय इकाई को प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय पुलिस टीम अल्पसंख्यक समुदाय में भय का माहौल पैदा कर रही है। यह सब देखकर देश के सभी हिस्सों में अल्पसंख्यक समुदाय में अन्याय की गहरी भावना पाई जाती है। मौलाना मदनी ने गृह मंत्री से मांग की कि खरगोन हिंसा की सच्चाई को सामने लाने के लिए एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कमेटी का गठन करें। साथ ही उन सभी लोगों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाए जिन्होंने जुलूस के दौरान हिंसा को हवा दी और जिसके कारण यह पूरी घटना हुई। कानून का पालन कराने वाली एजेंसियों के भेदभावपूर्ण रवैये का संज्ञान लेते हुए संपत्तियों के विध्वंस को तुरंत रोका जाए।

ज़रूरी ऐलान

आपकी ख़रीदारी अवधि पते की चिट पर अंकित है। अवधि की समाप्ति से पूर्व रक़म भेजने की कृपा करें।

रक़म भेजने के तरीक़े:-

❶ मनीआर्डर द्वारा ❷ Paytm या PhonePe द्वारा 9811198820 पर SHANTI MISSION
❸ ऑनलाइन हेतु बैंक खाते का विवरण
SBI A/c 10310541455
Branch: Indraprastha Estate
IFS Code: SBIN0001187

अपने प्रिय अख़बार साप्ताहिक शांति मिशन को इंटरनेट पर देखने के लिये लॉगऑन करें:
www.aljamiat.in —— www.jahazimedia.com
Mob. 9811198820 — E-mail: Shantimissionweekly@gmail.com

ख़रीदारी चन्दा

वार्षिक	Rs.130/-
6 महीने के लिए	Rs.70/-
एक प्रति	Rs.3/-

जानकारी के लिये सम्पर्क करें
साप्ताहिक
शांति मिशन
1, बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23311455

जमीअत ट्रस्ट सोसायटी की तरफ से मुद्रक, प्रकाशक मोहम्मद तैयब ख़ान ने शेरवानी आर्ट प्रिंटर्स, 1480, क़ासिमजान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवाकर मदनी हाल, न. 1, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित किया। संपादकः- मोहम्मद सालिम, फोनः- 23311455, 23317729, फैक्सः- 23316173